A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 02 जुलाई, 2024

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 295 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

04 -दंड नहीं, न्याय का विधान साबित होगा बदलाव

05 - 'पेपर लीक-व्यवस्था वीक' से टूटता भरोसा

06- जांच से मुक्त हुए मालवाहक वाहन, भ्रष्टाचार बैरियर बंद

07- नवीन आपराधिक कानून 2023 आज से लागू.



subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

# झारखंड- विस चुनाव से पहले अलग सरना धर्म की मांग क्यों ?

**नीरज सिन्हा**

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जनगणना में सरना आदिवासी धर्म के लिए एक अलग कोड के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई है। यह राज्य की आदिवासी आबादी के बीच एक लंबे समय से लंबित और भावनात्मक मांग है। प्रकृति पूजा पर केंद्रित, सरना आदिवासी धर्म मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों द्वारा पालन किया जाता है। हालांकि कोई अलग संहिता न होने के बावजूद भी 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने सरना को अपने धर्म के रूप में दर्ज कराया। अभी तक केवल हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के पास अपनी अलग संहिता या कोड है। एक अलग सरना कोड का समर्थन करने वालों का तर्क है कि यह आदिवासी परंपराओं और उनके धर्म की रक्षा करने और धर्मांतरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मांग झारखंड में कई आंदोलनों के केंद्र में रही है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 26.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी है।

नतीजतन, यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, झारखंड विधानसभा ने 2020 में एक विशेष सत्र में 'सरना आदिवासी धर्म' कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और उसकी सहयोगी कांग्रेस दोनों ने सरना कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह काम कर गया। भाजपा चुनावों में आश्वस्त थी कि उसे बढ़त मिलेगी, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने राज्य में एसटी के लिए आरक्षित सभी पांच सीटें जीत लीं। अब, नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ, भाजपा को सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना संभाग में एसटी के लिए 28 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जो 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में सत्ता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2019 में, भाजपा ने इनमें से केवल दो सीटें जीती थीं।

इसी पृष्ठभूमि में सोरेन ने 23 जून को पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली माझी परगना महल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया था। सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही इसमें आने वाली अड़चनों को दूर कर दिया है और केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने साजिश के तहत इसे लटकाए रखा है। उन्होंने प्रतिनिधियों से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे सरना कोड को लागू करवाएंगे। पार्टी के सांसद संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और भाजपा को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी ओर, भाजपा झामुमो और कांग्रेस पर केवल चुनावी लाभ और ईसाई वोट बैंक को लुभाने के लिए इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाती है।

राजनीतिक विश्लेषक रजत कुमार गुप्ता कहते हैं कि सोरेन ने आगामी विधानसभा चुनावों में आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए यह मुद्दा उठाया। लोकसभा चुनावों में आदिवासी लोग सरना कोड के मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और भाजपा का रुख सवालों के घेरे में था। चंपई सोरेन और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेर लिया था। , लेकिन इंडिया ब्लॉक को भी केंद्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है, अन्यथा यह उल्टा पड़ सकता है।

जल, जंगल और जमीन- प्रकृति के ये तीन पहलू सरना आस्था का मूल हैं। सरना के अनुयायी आमतौर पर प्रकृति-पूजक होते हैं। खूंटी जिले में सरना आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाली समिति सरना धर्म सोतो के पदाधिकारी मथुरा कंदीर कहते हैं, सभी आदिवासी गांवों में पूजा स्थल को सरना स्थल कहा जाता है। प्रकृति-उपासक सरना धर्म का पालन करते हैं और इसकी परंपराएं, रीति-रिवाज, जन्म से लेकर मृत्यु तक के त्यौहार और अनुष्ठान अन्य धर्मों से अलग हैं।÷आजकल, खूंटी जिले के विभिन्न आदिवासी गांवों में सरना धर्म सभाओं का आयोजन किया जाता है और सुख, शांति व समृद्धि के लिए 'भगवान सिंगबोंगा' से प्रार्थना की जाती है।

शून्यकाल में आदिवासी के लेखक अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं कि आदिवासी पहचान का दावा इतिहास में दिखता है और शुरू से ही राजनीतिक रहा है। पंकज कहते हैं कि 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासी धर्म का एक अलग कॉलम था और पूछते हैं कि जब संविधान सभी धर्मों और भाषाओं के संरक्षण और सम्मान की बात करता है तो इसे क्यों हटा दिया गया।

सरना कोड को 'पहचान का मुद्दा' बताते हुए झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि इसे लंबित क्यों रखा गया है और पिछले साल तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का हवाला दिया। पत्र में सोरेन ने कहा कि झारखंड की आदिवासी आबादी पिछले आठ दशकों में 38 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत रह गई है और इसका संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देश भर के आदिवासी कई सालों से अलग सरना/प्रकृति पूजा कोड की मांग कर रहे हैं।

झामुमो के एक अन्य महासचिव विनोद कुमार पांडेय कहते हैं कि सरना कोड और 'अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों' पर बैठक बुलाने के लिए 4 मार्च को अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू के सचिव को पत्र भेजा गया था, लेकिन पार्टी को बताया गया कि समय की कमी के कारण यह संभव नहीं है। हालांकि, भाजपा के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद समीर उरांव कहते हैं कि झामुमो और कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि उनकी मांग झारखंड के लिए है या भारत के सभी आदिवासियों के लिए। 'दोनों दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे दूसरे धर्म में धर्मांतरित आदिवासियों को उनके मूल धर्म में वापस लाने के पक्ष में हैं। हालांकि, कुछ आदिवासी आवाज़ें ऐसी भी हैं जो दोनों पक्षों की आलोचना करती हैं। आदिवासी सेंगेल अभियान झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में अलग सरना कोड और मूल निवासियों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है। इसके अध्यक्ष, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, झामुमो पर इस मुद्दे पर ÷दोषयुक्त÷ वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, जबकि भाजपा के लिए कहते हैं कि उनके पास आदिवासियों के लिए कोई प्यार नहीं है। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों को इस मुद्दे पर आश्वासन दिया था। अगर झामुमो और कांग्रेस गठबंधन इस मुद्दे पर गंभीर हैं, तो दोनों दलों को इसे संसद में ईमानदारी से उठाना चाहिए।

**( दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)**

विधानसभा परिसर में सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

# विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी खुद भरेंगे इनकम टैक्स

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के साथ अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी फैसला किया है कि वे वेतन भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि खुद जमा करेंगे। यह विधानसभा सचिवालय से जमा नहीं कराया जाएगा।

मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में फैसला लिया गया था कि मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि खुद मंत्री भरेंगे। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

- **मोहन कैबिनेट ने कलेक्टर को दिए पावर, गोवंश परिवहन करने वाले वाहन कर सकेंगे राजसात**

सोमवार को विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया- मंत्रिमंडल ने तय किया है कि मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स देंगे और इसके लिए 1972 में लाए गए विधेयक को बदलने संशोधन विधेयक को मंजूरी कैबिनेट ने दी है।सोमवार को विधानसभा भवन में डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई।

### लघु वनोपज संघ का पैसा आदिवासी कार्यों में ही होगा खर्च

विजयवर्गीय ने बताया कि लघु वनोपज आदिवासी समुदाय संग्रहीत करता है।इस पर राजस्व के रूप में बड़ा अंश राज्य शासन के पास एकत्र होता है और आदिवासियों को योजनाओं के रूप में दिया जाता है।कैबिनेट ने इस पर तय किया गया है कि जो पैसा इस मद में आएगा वह आदिवासी क्षेत्रों पर ही खर्च होगा।इस पैसे से आदिवासी क्षेत्रों की सड़कों और अन्य सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया जाएगा।इसे कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा।

### 107 करोड़ में होगा पुराने वल्लभ भवन का रेनोवेशन

कैबिनेट ने पुराने वल्लभ भवन जो वीबी-1 के नाम से जाना जाता है, उसके रेनोवेशन के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि वल्लभ ?भवन क्रमांक एक में दो बार आग लग चुकी है।नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार इस बिल्डिंग में सारे प्रावधान नहीं हैं।इसके लिए 107 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए हैं।इससे भवन में सुधार कार्य कराए जाएंगे।

### इन विधेयकों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

- मप्र विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।जिसमें राज्यपाल ने यह फैसला लिया है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहे जाएंगे।नलकूप खनन के बोरवेल खुले छोड़ने के लिए विधेयक लाया जाएगा।इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।खोदे गए नलकूप को खनन करने वाले को बंद करना है और नहीं किया तो बोर कराने वाले और ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई होगी।अगर सरकार ने बोर बंद किया तो इसकी राशि नलकूप खनन कराने वाले और ठेकेदार से की जाएगी।इस विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- कैबिनेट की बैठक में सोमवार को गोवंश परिवहन करने वालों पर कार्रवाई के अधिकार कलेक्टरों को दिए गए।जिस तरह आबकारी और माइनिंग में अवैध परिवहन करने पर कलेक्टरों को वाहन राजसात करने का अधिकार है, उसी तरह कलेक्टर गोवंश परिवहन करने वाले वाहन को राजसात कर सकते हैं।

# देश में खुद को हिंदू कहने वाले दिन-रात हिंसा करते हैं: राहुल

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत विवादित बयान दिया है। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं, वो चौबीसों घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा; नफरत, नफरत, नफरत; असत्य, असत्य, असत्य करते हैं। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के इस विचार पर आपत्ति जताई। हालांकि, जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, ना कि पूरे हिंदू समाज को। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए सिर्फ इतना कहा था, ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इतने पर राहुल गांधी बोलने लगे, नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं हैं। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा, शोर-शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने कहा है कि जो अपने आप को हिन्दू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं।

- शिव की तस्वीर दिखाकर नेता प्रतिपक्ष बोले-भाजपा हिंसा कराती है, ये हिंदू नहीं
- पीएम ने कहा-हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर, शाह बोले-माफी मांगें

## सुप्रभात

मेरे पास सीमित भाषा है,
और सीमित अर्थ
अपनी सीमित ध्वनियों
और सीमित भाव में
पर्याप्त अभिव्यक्त हूं मैं..
मेरे सीमित संपर्क और
और सीमित जन
थोड़े हैं..
जबकि उनका होना
आश्वस्ति से कम नहीं..
इस विज्ञापन समय में
प्रचार-प्रसार के स्खलन दौर में
अपनी सीमित सूचना में
मैं एक विज्ञप्ति भी नहीं..!
मैं अपने
चुटकी भर किस्सों में
भूली हुई कहानियों में
थोड़ी सी जान में
अधूरी पहचान में
चुराई गई नजरों में
और
उपेक्षित
व्यवहार में
उतना ही सीमित हूं
जितना आप अपनी हर
संभावना में
असीमित हैं..!
देखना
एक दिन आप
अपने असीमित शोर में विदा होंगे
और
मैं
अपने सीमित एकांत में लौट जाऊंगा..!

**सारंग उपाध्याय**

# फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी और 3 बच्चों के शव

### आलीराजपुर में पड़ोसी बोले-परिवार ने कभी परेशानी का जिक्र नहीं किया

**आलीराजपुर (नप्र)।** आलीराजपुर में पति-पत्नी और तीन बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं। घटना आलीराजपुर जिले के सांडवा थाना क्षेत्र के राउड़ी गांव की है। एसपी राजेश व्यास समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। एफएसएल की टीम जिला मुख्यालय से घटनास्थल के लिए निकल चुकी है।

पुलिस ने बताया कि राकेश पिता जागर सिंह, उसकी पत्नी ललिता, बेटी लक्ष्मी, बेटा प्रकाश और अक्षय के शव घर में ही फंदे पर लटके मिले। राकेश के चाचा सुबह घर पहुंचे तो इसकी जानकारी लगी। इसके बाद सांडवा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पोस्टमॉर्टम के लिए शवों को आलीराजपुर जिला अस्पताल लाया जा रहा है।

**रिश्तेदारों ने जताई हत्या की आशंका-** पड़ोसियों का कहना है कि राकेश किसान था।उसने या परिवार के किसी सदस्य ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया।वहीं, रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जताई है।पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।भाजपा मंडल अध्यक्ष जयपाल सिंह ने कहा, यह परिवार खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकता।यह हत्या है। पुलिस को इसकी जल्द जांच करना चाहिए।उन्होंने कहा कि परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से पूरे गांव में शोक है।

**एसपी बोले- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार-** एसपी राजेश व्यास ने बताया कि सुबह 7 बजे मामले की सूचना मिली थी। राकेश का घर उसके खेत के पास ही बना है।प्रकरण गंभीर है इसलिए एफएसएल की टीम बुलाई है।साइबर टीम को भी लगाया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 40.5 °c
न्यूनतम 36°c

# सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 02 जुलाई 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

## एंड्रॉयड फोन मंदिर में नहीं ले जा सकेंगे, 5-5 घंटे की होगी शिफ्ट

# पीतांबरी चौबंदी, सिर पर साफा..नई ड्रेस में रामलला के पुजारी

**अयोध्या (एजेंसी)।** अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू हो गया। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे। सिर पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया है। अब पुजारियों को पीतांबरी (पीली) चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। राम मंदिर के सहायक पुजारी संतोष कुमार तिवारी ने कहा- धर्मशास्त्रों के अनुसार, पुजारियों को ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, जिनमें पांव या सिर डालना हो। इसलिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। संतोष तिवारी ने ये भी बताया- पहले पुजारी सामान्य धोती-कुर्ता, कुर्ता-पायजामा पहनकर आ जाते थे। साफा (पगड़ी) और पीतांबरी (पीली) भी पहनते थे, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। नए ड्रेस कोड को राम मंदिर की पूजा में एकरूपता लाने के लिए लागू किया गया। इससे वरिष्ठ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी सहमत थे। रामलला के दरबार में 1 जुलाई से पुजारी

एंड्रॉयड फोन नहीं ले जाएंगे। संतोष तिवारी ने बताया- राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है। दरअसल, हाल के दिनों में राम मंदिर परिसर के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जिसको लेकर काफी हो-हल्ला मचा था। उनमें से एक पानी टपकने की तस्वीर भी शामिल थी। हालांकि, बाद में इस पर मंदिर ट्रस्ट की सफाई भी आई, जिसमें बताया गया था कि जिस जगह पर रामलला विराजमान हैं। वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। राम मंदिर ट्रस्ट सहायक पुजारियों को हर महीने 32 हजार रुपए तनख्वाह देता है। अभी मंदिर में एक मुख्य पुजारी के साथ 4 सहायक पुजारी हैं। हर सहायक पुजारी के साथ 5 ट्रेनी पुजारी सेवा करेंगे। इनकी सेवा सुबह 3.30 बजे से रात 11 बजे तक होगी। इनमें से पुजारियों की हर टीम को 5 घंटे की सेवा देनी होगी। यह नियम भी 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। रामलला की भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। संध्या आरती शाम 7.30 बजे और भोग आरती 8 बजे होगी। रामलला की शयन आरती रात 10 बजे होगी, जिसके बाद गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाएंगे।

## संक्षिप्त समाचार

### आजादी के 77 साल बाद देश में न्याय व्यवस्था हुई स्वदेशी

- 3 नए आपराधिक कानूनों पर शाह ने कहा-अब दंड की जगह न्याय मिलेगा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह ने कहा

कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। शाह बोले- अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा। साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। गृहमंत्री के मुताबिक देशभर में 22.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ट्रेनिंग 12 हजार से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स ने दी है। लोकसभा में 9.29 घंटे चर्चा हुई, उसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। शाह ने कहा कि यह भी झूठ है कि विधेयक को सांसदों को बाहर भेजे जाने के बाद लाया गया।

### अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत

- तालिबान के नेता मौजूद रहे, यूएन ने सफाई दी-मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं

**काबुल (एजेंसी)।** कतर की राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत 25 देश शामिल हुए। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हों। इससे पहले वे

यूएन की हर उस बैठक का बहिष्कार करते रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई हो। हालांकि, यूएन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल उठाए। इन संगठनों की मांग है कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा तब तक न तो उससे बात की जाए और न उन्हें मान्यता मिले। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह शामिल हुए। हालांकि, इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोहा में थे पर वे बैठक में नहीं गए। भारत अभी तालिबान के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।

## देश के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है एक जुलाई का दिन - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

- मुख्यमंत्री ने नई न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज एक जुलाई का दिन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तीन कानूनों को बदलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई व्यवस्था का क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज से प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रदेश के नाकों में गुजरात पैटर्न पर चैक-पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही। बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में भारतीय न्याय पद्धति और अवधारणा तथा पंच परमेश्वर की परम्परा के आधार पर न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी बधाई के पात्र हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लगभग चार सौ घंटे के परिश्रम व विभिन्न बैठकों तथा व्यापक विचार-विमर्श के बाद नए कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप प्रदान किया है। अब भारतीय दंड संहिता को हमारी न्याय परम्परा से जोड़ते हुए न्याय संहिता कहा जाएगा। अंग्रेज तो दंड देने के अधिकारी थे, लेकिन अब हमारी व्यवस्था न्याय की परम्परा को स्थापित करेगी। इसमें आँख पर पट्टी बांधकर नहीं अपितु आँख खोलकर न्याय होगा।

### दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार और पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव को जन्म दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दीं।

## जेल में बंद कश्मीरी सांसद को मिली राहत

- लोकसभा में शपथ लेने पर एनआईए ने जताई सहमति

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** एनआईए ने कश्मीरी नेता और लोकसभा चुनाव में जीते निर्दलीय सांसद राशिद इंजीनियर को 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमित दे दी है। एनआईए के वकील ने

दिल्ली की अदालत में कहा जेल में बंद कश्मीरी नेता राशिद को मीडिया से बात न करने जैसी शर्तों के आधार पर संसद में सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देनी चाहिए। एनआईए द्वारा कहा गया है कि सहमति शर्तों पर ही निर्भर है। इस मामले में कल दिल्ली की पटियाला कोर्ट आदेश जारी कर सकता है।

## होटल में बंद खिलाड़ी लाइन में लगकर कर रहे डिनर

- बेरिल चक्रवात की वजह से बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया

**बारबाडोस (एजेंसी)।** टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम बारबाडोस में फंस गई है। टीम को एक जुलाई को वहां से रवाना होना था लेकिन ब्रिजटाउन में एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। यह सब चक्रवात की वजह से हो रहा है। हेरिकेन बेरिल काफी खतरनाक हो गया है। यह कैटेगरी चार में तब्दील हो चुका है। अगले कुछ घंटों में यह बारबाडोस से टकरा सकता है और वहां लगातार बारिश भी हो रही है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरह होटल में पैक हो चुके हैं। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार होटल में भी लिमिटेड स्टाफ ही हैं। भारतीय खिलाड़ियों को कतार में लगकर पेपर की प्लेट में डिनर करना पड़ा है। बारबाडोस में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। अभी किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। टीम इंडिया के आने पर भी कोई अपडेट नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, बेरिल के 130 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से विंडवार्ड द्वीप समूह से टकराने की आशंका है। तूफानी लहर और भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

# भारत ने बनाया दुनिया का 'सबसे तगड़ा' विस्फोटक

- ब्रह्मोस वाले से भी ज्यादा घातक, दुनिया में मचेगी खरीदने की होड़ ● मेक इन इंडिया अभियान के तहत निर्मित सेबेक्स-2 का सफल परीक्षण

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत लगातार नए-नए आयाम हासिल कर रहा है। ताजा उपलब्धि से न केवल भारतीय सेना की मारक क्षमता में भारी इजाफा होने जा रहा है बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र को भी पंख लगने की पूरी उम्मीद है। यह उपलब्धि बेहद घातक विस्फोटक बनाने में हासिल हुई है। भारत ने सेबेक्स 2 नामक विस्फोटक तैयार कर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। इस विस्फोटक के बारे में इतना कहा जा सकता है कि यह परमाणु आधारित नहीं है, लेकिन इसकी विनाशकारी क्षमता बहुत अधिक है। कोई विस्फोटक कितना घातक है, इसका आकलन टीएनटी (ट्राइनाइट्रोटोलुइन) के आधार पर किया जाता है। टीएनटी एक मानक है जिसके अनुसार तय होता है कि किसी विस्फोटक में कितनी तबाही करने की क्षमता है। इस पैमाने पर सेबेक्स 2 की क्षमता दोगुने से भी थोड़ा ज्यादा है। भारत के सेबेक्स 2 का परफॉर्मेंस इतना हाई है कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु विस्फोटकों में से एक बन गया है। नौसेना ने सेबेक्स 2 का व्यापक परीक्षण करने के बाद इसके इस्तेमाल के लिए ओके कर दिया

है। नई विधि से तैयार विस्फोटक सेबेक्स 2 की खासियत यह है कि यह बिना वजन बढ़ाए बम, तोपखाने के गोले और वॉरहेड्स की विनाशकारी शक्ति में जबर्दस्त वृद्धि के साथ क्रांति लाने में सक्षम है। इसी वजह से इसकी पूरी दुनिया में मांग हो सकती है। यानी, भारत के लिए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया बाजार खुलने जा रहा है। दरअसल, दुनिया भर की ताकतें मौजूदा हथियार प्रणालियों को ज्यादा से ज्यादा घातक बनाने में जुटी हुई हैं। नौसेना ने सेबेक्स 2 का मूल्यांकन, परीक्षण और प्रमाणन रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के तहत किया है। अधिकारियों ने कहा, विस्फोटक के विकास से इस्तेमाल में आने वाले हथियारों और गोला-बारूद की क्षमता एवं दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फाइनल सर्टिफिकेशन पिछले सप्ताह पूरा हो गया था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि जितनी ज्यादा टीएनटी, विस्फोटक उतना ही घातक होता है। भारत में अभी इस्तेमाल किया जा रहा सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विस्फोटक ब्रह्मोस मिसाइल के वॉरहेड में इस्तेमाल हो रहा है। यह लगभग 1.50 के टीएनटी का है। वहीं, दुनिया भर में पारंपरिक वॉरहेड में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश विस्फोटकों की टीएनटी तुल्यता 1.25-1.30 होती है। सूत्रों ने बताया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (ईईएल) ने मेक इन इंडिया पहल के तहत विस्फोटक सेबेक्स 2 को तैयार किया है।

## भारत से बढ़ी 'दूरी' तो टेंशन में आया अपना दोस्त रूस

पीएम मोदी की यात्रा से बदलेंगे रिश्ते! दुनिया की टिकी नजर

### यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस यात्रा पर जा रहे पीएम मोदी

**मास्को (एजेंसी)।** यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पीएम मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस में रहेंगे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पुतिन और मोदी इस मुलाकात के दौरान रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों पर जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में 'दूरी' बढ़ रही है। पीएम मोदी और पुतिन भारत और रूस के बीच व्यापार पर बात कर सकते हैं जो तेल के आयात की वजह से बहुत बढ़ गया है। भारत और रूस पेमेंट के मुद्दे को आसान बनाने पर बात कर सकते हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से फंसा हुआ है। रूस और चीन की दोस्ती बढ़ रही है, यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी साल 2015 के बाद पहली बार मास्को पहुंच रहे हैं। इसे भारत और रूस के बीच दशकों से हो रहे वार्षिक शिखर सम्मेलन की फिर से शुरुआत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने साल 2017, 2018, 2019 में रूस की यात्रा की थी।

## निचली अदालत में लगे झटके के बाद हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

- गिरफ्तारी को बताया अवैध, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें पिछले दिनों ही जेल से ही सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है, जिसके

बाद कोर्ट ने उन्हें 12 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। अब निचली अदालत के फैसले को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध भी बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

## एमवीए साथ मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

### शरद पवार बोले-गठबंधन की छोटी पार्टियों संग आगे बढ़ेंगे

**मुंबई (एजेंसी)।** महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस, एनसीपी (शरद) और शिवसेना (यूबी) महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी में भी शामिल हैं। रविवार को एनसीपी (शरद) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना (यूबी) और उनकी पार्टी मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे राज्य विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करें, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन का हिस्सा थे। वहीं, महाराष्ट्र में एनडीए की महायुति वाली सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे पोस्ट शेयर कर खुशी जाहिर की। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे का जिक्र किया। पवार ने कहा- विपक्ष महाराष्ट्र के लोगों के सामने एक सामूहिक चेहरा रखेगा। राज्य में बदलाव की जरूरत है और इसे पूरा करना विपक्षी गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है। शरद पवार ने आगे कहा कि महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य मछली की

आंख थी, इसलिए हमारी नजरें महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों पर टिकी हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी।

## बरकोटी घाटी पर ट्रैक्टर में घुसी यात्री बस, तीन घायल

● सागर में ट्राले से सड़क पर गिरा ट्रैक्टर,पीछे से आ रहा ट्रैक्टर और फिर यात्री बस टकराई

**सागर (नप्र)।** सागर के गौरझामर थाना क्षेत्र में स्थित बरकोटी घाटी पर यात्री बस ट्रैक्टर से टकरा गई। दुर्घटना में बस ड्राइवर समेत तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सागर-नरसिंहपुर हाईवे पर ट्रैक्टरों से लदा ट्राला जा रहा था। तभी बरकोटी घाटी पर गुरु चौपड़ा के पास ट्राले से एक ट्रैक्टर सड़क पर अचानक गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहा ईंट से भरा ट्रैक्टर-ट्राली उक्त ट्रैक्टर से टकरा गया। तभी पीछे से आ रही यात्री बस भी ट्रैक्टर में जा घुसी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बस से यात्रियों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही गौरझामर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। ट्राला को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है।

### जैसीनगर से नरसिंहपुर जा रही थी बस

दुर्घटनाग्रस्त हुई यात्री बस जैसीनगर से सवारियां लेकर नरसिंहपुर जा रही थी। बस बरकोटी ट्रेवल्स की है। घटना के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे। हालांकि हादसे में यात्रियों को चोट नहीं आई है। बस के ड्राइवर के हाथ में गंभीर चोट लगी है। घटना में घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

## भोपाल जेल के सामने तालाब में मिली युवक की लाश

● परिजन बोले पुलिस ने जेल भेजा था, दो दिन बाद सीधे मौत की सूचना मिली

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल सेंट्रल जेल गांधी नगर के सामने तालाब में एक युवक की लाश रविवार को मिली। देर रात उसकी शिनाख्त की जा सकी। सोमवार को बॉडी का पीएम कराया गया। इधर, परिजन का आरोप है कि 27 जून को उसे गोविंदपुरा पुलिस ने जेल भेजा था। इसके बाद सीधे उसकी मौत की सूचना मिली। हमें हत्या का संदेह है। गांधी नगर पुलिस का कहना है कि मामले में मर्ग कायम कर लिया है। एफएसएल की टीम से स्पॉट का मुआएना करा लिया है। पीएम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। गांधी नगर थाने के एसआई कन्हैयालाल यादव ने बताया कि प्रमोद चौधरी पिता प्रदीप चौधरी (29) निवासी अन्ना नगर गोविंदपुरा सब्जी का कारोबार करते थे। गुरुवार को उनका पत्नी से विवाद हुआ था। इसकी शिकायत पत्नी ने थाना गोविंदपुरा में की थी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। धारा 151 के तहत कार्रवाई कर अगले दिन जेल भेज दिया। 29 जून को उनकी रिहाई जेल रिकार्ड के अनुसार हो चुकी थी। 30 जून रविवार को जेल के सामने तालाब में उनकी लाश मिली। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। तब उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। रविवार की रात को बॉडी की शिनाख्त की जा सकी। शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है।

### परिजन बोले प्रमोद की हत्या की गई

मृतक के मामा राजेश चौधरी ने बताया कि प्रमोद को गोविंदपुरा पुलिस ने जेल भेजा था। आपसी विवाद के बाद पत्नी ने उनकी शिकायत थाने में की थी। परिवार में किसी ने उसकी जमानत नहीं ली थी। उसकी जमानत किसने ली इसकी जानकारी हमें नहीं है। कब रिहाई हुई, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। रविवार की रात को गोविंदपुरा पुलिस ने ही हमें मौत की सूचना दी है। हमें संदेह है कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। उसकी हत्या की गई है।

### शराब ज्यादा पीता था युवक

प्रमोद के परिजनों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि वह शराब पीने के आदि थे। नशे में आए दिन पत्नी से विवाद किया करते थे। प्रमोद मूल रूप से नरसिंहपुर के रहने वाले थे। लंबे समय से भोपाल में रहकर कारोबार कर रहे थे। उनकी शादी आठ साल पहले पूजा से हुई थी। दोनों की दो संतान 7 साल की प्रिंसी और 3 साल का प्रजुल है। सोमवार की दोपहर को पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

### स्ट्रीट डॉग को फटकारने पर विवाद

## पड़ोसी परिवार और साथियों ने वृद्ध पति-पत्नी सहित 6 को जमकर पीटा, पुलिस पर भी लगे आरोप

**भोपाल (नप्र)।** अवधपुरी इलाके की वल्लभ नगर कॉलोनी में स्थित एक घर के सामने स्ट्रीट डॉग हर रोज गंदगी कर जाता था। इससे गुस्साए एक युवक ने शुक्रवार को डॉग को फटकार कर घर के सामने से भगा दिया। यह देख पड़ोस का एक युवक गुस्सा हो गया। इससे दोनों युवकों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में युवक ने अपने पिता भाई और दोस्तों को बुलाकर कुत्ते को डांटने वाले युवक के घर हमला कर दिया। पहले कुत्ते को फटकारने वाले युवक की धुनाई की, बाद में बुजुर्ग पति-पत्नी सहित उनके बेटे, नवासी सहित एक अन्य को बेरहमी से मारा। हमले में सभी को गंभीर चोट आई हैं। इस मामले में पुलिस ने बेहद साधारण धाराओं में एफआईआर की है। आरोप है कि अगले दिन पुलिस ने आरोपी पक्ष की शिकायत पर परिवार के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। पीड़ित परिवार ने अवधपुरी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया है।

## टीवी चैनल द्वारा किया गया उद्यमियों का सम्मान

# प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर भी होगी चर्चा : मुख्यमंत्री

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के लघु उद्यमियों की सहायता के लिए राज्य शासन तत्पर है।लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। इस माह जबलपुर में हो रही समिट में उद्योग के नवीन क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रण दिया जाएगा। खनन आधारित उद्योगों, ग्रामीण कुटीर उद्योगों और रेडीमेंट गारमेंट उद्योग के विकास की काफी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए क्षेत्र चिन्हित कर लघु उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एनडी टीवी चैनल की ओर से स्थानीय होटल मैरियट में एमएसएमई समिट एवं उद्यमियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर चैनल की तरफ से स्थानीय संपादक श्री अनुराग द्वारी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि एक समय उन्होंने उज्जैन में चाय-नाश्ते की होटल का संचालन करते हुए एक व्यवसायी की भूमिका निभाई है। किसी भी कार्य व्यवसाय को परिश्रम और संयम के साथ साफ-सुथरे ढंग से संचालित कर आत्मनिर्भर होने की भावना किसी भी व्यवसायी या उद्यमी को जीवन में सफलताएं दिलवाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मंत्रीगण द्वारा आयकर की राशि जमा किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज विधानसभा में राज्य सरकार के इस निर्णय का सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर स्वागत किया गया। स्पीकर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विशेष उल्लेख कर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने स्वयं भी इनकम टैक्स खुद जमा करने के संकल्प से अवगत करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे भी अपना आयकर स्वयं जमा करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में टोल नाकों से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में पेपर लीक के मामलों में दोषी व्यक्ति को दस वर्ष की सजा का निर्णय लिया गया है। विधान सभा में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सदैव चर्चा के लिए तैयार हैं। माननीय सदस्यों द्वारा संयम और मर्यादा से सभी नियमों के पालन के प्रति गंभीर रहते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने एमएसएमई समिट में श्री राहुल पांडे, श्री रोहित सोमानी, श्री अर्पित जैन और अन्य उद्यमियों का सम्मान किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत किया गया।

## सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून:सीएम डॉ. मोहन यादव

**भोपाल (नप्र)।** भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे । इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेज़ेन्टेटिव, लंदन गैज़ेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का ज़िक्र है।

## कुलपति होंगे कुलगुरू, इस शब्द में सम्मान और आत्मीयता का भाव है :सीएम डॉ. यादव

● गौवंश परिवहन और ट्यूब वेल खुला छोड़ने वालों को नहीं बख्शेंगे

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों के कल्याण और उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। निरंतर लिए जा रहे ऐसे फैसलों से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था से जुड़े आवश्यक सुधार भी हो रहे हैं, इस क्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरू का संबोधन देने का निर्णय लिया गया। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव भी निहित है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा इन निर्णय का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज टीवी चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि जुलाई माह में ही गुरू पूर्णिमा पर्व भी आ रहा है। मध्यप्रदेश में कुलपति को कुलगुरू बनाने के निर्णय के संबंध में अन्य राज्यों द्वारा भी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए इस निर्णय का प्रारूप चाहा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गोवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन कई बार न्यायालय से छूट जाते हैं। नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के प्रकरण में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त होंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ट्यूब वेल खनन के बाद बिना ढक्कन के खनन स्थल होने से छोटे बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। प्रायः बच्चों को बचाया जाना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। ट्यूब वेल खनन के बाद उसे छोड़ देने वाले व्यक्तियों की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

# मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल

## मानहानि मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला, पाटकर बोलीं- सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता

**बड़वानी (नप्र)।** दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर को पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें सक्सेना की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया,साथ ही कोर्ट ने उम्र का हावला देने वाली दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केस 25 साल तक चला। हालांकि, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के तहत उनकी सजा को 1 अगस्त तक निलंबित कर दिया, ताकि वह आदेश के खिलाफ अपील कर सके। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मेधा पाटकर ने कहा- सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, हम केवल अपना काम करते हैं। हम अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। बता दें, 30 मई को वीके सक्सेना की ओर से पेश वकील ने मेधा को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल

की कैद की सजा का प्रावधान है। 24 मई को साकेत कोर्ट ने मेधा को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने मेधा पाटकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट के फैसले पर मेधा पाटकर ने कहा- सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, हम केवल अपना काम करते हैं। हम अदालत के फैसले को चुनौती देंगे।

**कोर्ट ने मेधा को क्या कहते हुए दोषी बताया:** कोर्ट ने कहा था, ये साफ हो गया है कि आरोपी मेधा ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ गलत जानकारी के साथ आरोप लगाए। बता दें, 25 नवंबर 2000 को मेधा पाटकर ने अंग्रेजी में एक बयान जारी कर वीके सक्सेना पर हवाला के जरिए लेनदेन का आरोप लगाया था और उन्हें कायर कहा था। मेधा पाटकर ने कहा था कि वीके सक्सेना गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहे थे। ये बयान वीके सक्सेना की ईमानदारी पर सीधा-सीधा हमला था। मेधा ने कहा था- सक्सेना ने शारीरिक हमला भी किया था मेधा पाटकर ने कोर्ट में अपने बचाव में कहा था कि वीके सक्सेना वर्ष 2000 से झूठे और मानहानि वाले बयान जारी करते रहे हैं। उन्होंने 2002 में उन पर शारीरिक हमला भी किया था, जिसके बाद मेधा ने अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज कराई थी।

# म.प्र.में अगले 5 दिन तक आंधी, बारिश और गरज-चमक

● इंदौर-उज्जैन में आज भी बादल-बारिश का दौर, 15 जुलाई तक पूरा प्रदेश भीगेगा

**भोपाल (नप्र)।** देश में पांच साइक्लोनिक सिस्टम और ट्रफ लाइन एक्टिव हैं। इसका असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई जबकि सोमवार को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर-उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भी मौसम बदला रहा और बारिश हुई। भोपाल में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग, भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि 3 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। 15 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। डॉ. सिंह ने बताया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। पिछले 24 से 48 घंटे में कई जगहों पर अति भारी बारिश भी हुई है। अगले 5 दिन तक आंधी, बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। 3 जुलाई से पूर्वी बंगाल की खाड़ी से बारिश की एक्टिविटी तेज होगी। इससे पूर्वी हिस्से के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। 4 जुलाई को कई जिले भीगेंगे।

### नौगांव में 2.9 इंच बारिश

रविवार को छतरपुर जिले के नौगांव में सबसे ज्यादा 72 मिमी यानी 2.9 इंच पानी गिर गया। मंडला में सवा इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं, रीवा में 2.1 इंच बारिश हुई। भोपाल-टीकमगढ़ में 1 इंच के करीब बारिश दर्ज की गई। धार, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, रायसेन, रतलाम, दमोह, जबलपुर, सागर, उमरिया, मलाजखंड में भी पानी गिरा। रात में प्रदेश के कई शहरों में तेज बारिश का दौर चलता रहा।

# खंडवा में हत्या के आरोपी की पत्नी ने किया सुसाइड

### टीआई बोले- नशा करती थी महिला, पति ने वन समिति अध्यक्ष को मारी थी गोली

**खंडवा (नप्र)।** खंडवा में वन समिति अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की पत्नी ने फांसी लगा ली है। फिलहाल, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। महिला का हत्यारा पति फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि महिला ने रविवार रात में सुसाइड किया है। वो शराब का नशा करती थी। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मांधाता (ओंकारेश्वर) थाना क्षेत्र के गांव जिल्हार का है। यहां ललिताबाई ने फांसी लगा ली। टीआई अनोक सिंह सिंधिया का कहना है कि, पुलिस को सोमवार सुबह 9 बजे सूचना मिली थी। घटनास्थल पर महिला का शव रस्सी पर लटका हुआ था। महिला का पति सूरसिंग हत्या का आरोपी हैं। उसने 17 जून को गांव में वन समिति अध्यक्ष धनसिंह मिश्रा को गोली मारी दी थी। धनसिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तब से

महिला का पति सूरसिंग फरार हैं। इधर, ललिताबाई का मामला संदिग्ध है। हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच होगी। शव बरामद कर ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, महिला का पति सूरसिंग हत्याकांड में फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जगह-जगह दबिश दी गई। जल्द ही वह पुलिस गिरफ्त में होगा। एक पखवाड़े पहले ललिता के पति ने मारी थी गोली, अध्यक्ष की हो गई थी मौत खंडवा में एक पखवाड़े पहले हुए गोलीकांड में घायल वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी पांच दिन बाद मौत हो गई थी। मांधाता पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित की मौत की सूचना मिलने के बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई हैं। घटना मांधाता थाना क्षेत्र के ग्राम जिल्हार की थी। धनसिंह पिता बद्रीविशाल मिश्रा को उन्हीं के ममेरे भाई सुरसिंग ने गोली मार दी थी। धनसिंह गांव की वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे। शासन द्वारा भेजी गई तेंदुपत्ता मजदूरी की राशि को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद सुरसिंग ने 12 बोर की बंदूक से धनसिंह पर फायर कर दिया था। बंदूक से निकली गोली धनसिंह की कमर के आर-पार हो गई थी। परिजन उन्हें सनावद अस्पताल ले गए। जहां से इंदौर रेफर किया गया था। जहां इलाजरत धनसिंह ने पांचवे दिन दम तोड़ दिया था।

संपादकीय

# नए कानून– क्या ढर्रा भी बदलेगा?

देश भर में 1 जुलाई से तीन नई फौजदारी कानून संहिताएं न्याय संहिता के रूप में लागू हो गई हैं। दिल्ली और मप्र में नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था में कानून को सख्त बनाने के साथ साथ अपराध और न्याय से जुड़ी सभी एजेंसियो को जवाबदेह भी बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि नई व्यवस्था असरकारी साबित हो, इसके लिए सरकारी तंत्र का ढर्रा भी बदलेगा? क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव नहीं नजर आया तो नया कानून नई बोतल में पुरानी शराब ही साबित होगा। पिछले साल दिसंबर में जब ये कानून संसद में पारित हुए थे, तब सरकार ने दावा किया था कि इससे देश में औपनिवेशिक काल के फौजदारी कानूनों की समाप्ति और आजाद भारत के नए, संशोधित और सख्त कानूनो के युग का सूत्रपात होगा। यह देश पर अंगरेजों के राज की प्रतीकात्मक समाप्ति भी है। इसके तहत अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है। ये कानून अपने पूर्ववर्ती कानूनों से कई मामलों में अलग और बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से हैं। मसलन नये कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें 'जीरो एफआईआर', पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है। लेकिन नए कानूनों में एक गुणात्मक बदलाव ये है कि ये कानून अब अपराधी को दंड देने के ज्यादा फरियादी को न्याय देने की मंशा से ज्यादा प्रेरित हैं। इसमें समयबद्धता भी तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि कहा कि नये कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे जबकि अंग्रेजों (देश पर ब्रिटिश शासन) के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गयी थी। नई व्यवस्था एक जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज़्यादा ज़िला न्यायालयों और 16 हजार पुलिस थानों में लागू कर दी गई है। अब से संज्ञेय अपराधों को सीआरपीसी की धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। नये कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। नई भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल गया है। जैसे- शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल। नस्ल, जाति- समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा, छिनैती के लिए तीन साल तक की जेल। यूएपीए जैसे आतंकवाद-रोधी क़ानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। जांच-पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात हर थाने में सब इंसपेक्टर के रूप में नोडल अधिकारी की नियुक्ति है। जहां तक मप्र की बात है तो नए कानून की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीसीटीएनएस में नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुका है। नए कानूनो की मंशा पर सवाल भले न हो, लेकिन असली सवाल यह है कि कानून पालन कराने वाली एजेंसियों के काम काज का ढर्रा भी बदलेगा या नहीं?

नजरिया

प्रमोद भार्गव

*लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।*

# दंड नहीं, न्याय का विधान साबित होगा बदलाव

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आहत होकर अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके मददगारों को दंड देने की दृष्टि से अनेक औपनिवेशिक कानून लागू किए थे। इनमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी राज का पर्याय बने तीन मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इन कानूनों के षीर्शक में ही 'दंड' की प्रधानता है। मसलन इन कानूनों की चपेट में जो भी आएगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। दंड के मनोविज्ञान से ही निर्दोश भयभीत हो जाया करते हैं। इस भय से मुक्ति का प्रावधान करने की दृश्टि से 'न्याय' षब्द का प्रयोग कानून के षीर्शकों में किया गया है। न्याय षब्द ही इस अर्थ का प्रतीक है कि यदि आपसे भूलवष कोई अपराध हो भी गया है तो आप न्याय के भागीदार होंगे।

अंग्रेजों के बनाए हुए दंड के विधान वाले ये कानून वास्तव में उन अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जिनके विरुद्ध आम भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अतएव अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दमन और लूट को सुरक्षा देने वाले कानून 1 जुलाई 2024 से खत्म हो जाएंगे।

फिरंगी हुकूमत ने कानून भारतीयों को अधिकतम दंड देने की मानसिकता से बनाए गए थे, जबकि कोई भी विधि सम्मत प्रक्रिया दंड की अपेक्षा न्याय के सारोकारों से जुड़ी होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय न्याय व्यवस्था के सिलसिले में कहा जाता रहा है कि यहां न्याय नहीं निराकरण होता है। इन कानूनों के लागू होने के साथ दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली भारत की होगी, क्योंकि अब इनकी आत्मा में भारतीयता निहित कर दी गई है। वैसे भी भारत में न्याय की अवधारणा बहुत पुरानी है और ये कानून उसी अवधारणा की भावना पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच प्रण किए थे, इनमें एक प्रण गुलामी की निशानियों को खत्म करना भी था। कानून संबंधी पारित विधेयक उसी परिप्रेक्ष्य में हैं। इन नए कानूनों के अंतर्गत दंड अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए दिया जाएगा। ये नए कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अब नए कानून में नाबालिग से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजद्रोह कानून ब्रिटिश सत्ता को कायम रखने के लिए था, इसे अब खत्म किया जा रहा है। कुछ प्रचलित धाराओं की संख्या भी बदली गई है।

प्रमुख रूप से अंग्रेजी राज का पर्याय बने तीन मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कहा जाएगा। 164 साल पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जो बीएनएस-2023 में 358 रह जाएंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ाई गई है। पहली बार छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है। साफ है, पीड़ितों के साथ न्याय पर फोकस किया गया है। 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कहा जाएगा। इसमें 47 नई धाराओं के साथ अब कुल 531 धाराएं होंगी। पहले धारा 154 में होने वाली प्राथमिकी नए कानून के तहत धारा-173 में दर्ज की जाएगी। अब पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता में से 'दंड को हटाकर नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। पुराने कानून में 167 धाराएं थीं, जो अब 170 रह गई हैं। इस कानून को तकनीक और फॉरेंसिक आधार पर तैयार किया गया है। ताकि सजा का प्रतिषत 90 प्रतिषत तक पहुंच जाए। बढ़ते साइबर अपराधों के संदर्भ में इस कानून की अहम् भूमिका जताई जा रही है। नए प्रारूप में धारा 150 के तहत आरोपी को सात साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। मॉब लीचिंग यानी उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा के लिए अलग से सजा का प्रावधान किया गया है। इसे पंथ निरपेक्ष रखा गया है। क्योंकि कभी-कभी चोर को भी भीड़ मार देती है। झारखंड और अन्य कई अषिक्षित क्षेत्रों में महिलाओं को डायन बताकर समूह मार देता है। इन हत्याओं पर अब मॉब लीचिंग कानून लागू होगा। अभी तक ऐसे मामलों में हत्या की धारा 302 और दंगा या बलवा की धाराएं 147-148 के तहत कार्यवाही होती है।

नाबालिग से दुष्कर्म या पहचान छिपाकर किए गए दुष्कर्म के आरोप में 20 साल का कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। विरोध नहीं करने के अर्थ का आशय सहमति नहीं निकाला जाएगा। मौजूदा स्थिति में नाबालिग से दुष्कर्म पर न्यूनतम सजा में सात साल की व्यवस्था है। इसी तरह राज्यों को अब असली पहचान छिपाकर संबंध बनाने वाले अपराधियों के लिए 'लव जिहाद' जैसा पृथक कानून बनाने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावित कानून में गलत पहचान बताकर नौकरी, पदोन्नति और अन्य प्रलोभन दिलाने के झूठे वादे कर दुष्कर्म के अंजाम को सजा के दायरे में लाया गया है। लव जिहाद इसी के अंतर्गत आएगा। देश में पहली बार छोटे-मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का क्रांतिकारी प्रावधान किया गया है। इन अपराधों में नशे में हंगामा और पांच हजार से कम की चोरी करने के आरोप में सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। ऐसी सजा में सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ग्वालियर ने इस तरह की सजाएं सुनाई हैं।

सबसे बड़ा परिवर्तन 1860 में अस्तित्व में आए औपनिवेषिक कानून 'राजद्रोह' में किया गया है। राजद्रोह कानून से 'राजद्रोह' षब्द विलोपित करके 'देषद्रोह' किया है। क्योंकि अब देष स्वतंत्र हो चुका है। अतएव लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। यह नागरिक का अधिकार है। इसके औचित्य पर लगातार सवाल उठते रहे थे। संसद में भी इस धारा के औचित्य पर कई बार प्रष्नचिन्ह खड़े किए गए हैं। लेकिन बदलाव के इस प्रस्ताव से पहले कोई भी सरकार ने इस कानून में परिवर्तन की हिम्मत नहीं जुटा पाई। संप्रग सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब 2012 में राज्यसभा में प्रस्तुत एक निजी विधेयक में सांसद डी राजा ने कहा था कि 'देश में चले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के दमन और उन पर अमानुषिक अत्याचार के लिए फिरंगी हुकूमत ने 1860 में देशद्रोह का कानून बनाया था। इसे और कठोर 1870 में धारा 124-ए को दण्ड प्रक्रिया संहिता में शामिल कर दिया गया था, लिहाजा इस कानून में अब बदलाव की जरूरत है।' लेकिन इस निजी विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल यही वह कालखंड था, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूरे राष्ट्र में एकजुटता के साथ उभरा था। इसमें आमजन की बड़ी संख्या में भगीदारी थी। इसी आमजन को दंडित करने के लिए ही इस दमनकारी कानून को वजूद में लाया गया था।

यह सब जानते हुए भी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने धारा 124-ए को 'आतंकवाद, उग्रवाद और सांप्रदायिक हिंसा जैसी देषद्रोही समस्याओं से निपटने के लिए आवष्यक और संविधान सम्मत' बताया था। सरकार ने इस समय संसद में यह भी स्पष्ट किया था कि समुचित दायरे में रहकर सरकार की आलोचना करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जब आपत्तिजनक तरीकों का सहारा लिया जाए, तब यह धारा प्रभावी हो सकती है।' तब बहस में भाजपा समेत कई दलों के सांसदों ने मौजूदा सरकार के इस रुख का समर्थन किया था। इस धारा के आतंकवाद और उग्रवाद के परिप्रेक्ष्य में चले आ रहे महत्व के चलते ही, इसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी नहीं हटा पाए थे, जबकि वे इसे हटाए जाने के पक्ष में थे।

धारा 124-ए के अंतर्गत लिखित या मौखिक षब्दों, चिन्हों प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष तौर से नफरत फैलाने या असंतोश जाहिर करने पर देषद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है।

इस धारा के तहत दोशी पर आरोप साबित हो जाए तो उसे तीन साल के कारावास तक की सजा हो सकती है। 1962 में षीर्श न्यायालय के सात न्यायाधीषों की खंडपीठ ने 'केदारनाथ बनाम बिहार राज्य' प्रकरण में, राजद्रोह के संबंध में ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि 'विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अव्यवस्था फैलाने या फिर कानून या व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति या मंषा हो तो उसे राजद्रोह माना जाएगा।' इसी परिभाशा की परछाईं में हार्दिक पटेल बनाम गुजरात राज्य से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'यदि कोई व्यक्ति अपने भाशण या कथन के मार्फत विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने का आवाहन करता है तो उसे राजद्रोह माना जाएगा।' अदालत के इन फैसलों के अनुक्रम में किसी अन्य देष की प्रषंसा, परमाणु संयंत्रों का विरोध, राश्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होना, जैसे आचरण जरूर राजद्रोह नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन 'भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार,' जैसे नारे न केवल राजद्रोह हैं, बल्कि राश्ट्रद्रोही भी है।' इस परिप्रेक्ष्य में यह समझ लेना भी जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 19-1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जरूर देता है, लेकिन इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है।

नए कानून में पहली बार आतंकवाद की इबारत को पारिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति देष की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को संकट में डालने के इरादे से कोई कृत्य करता है तो उसे नए कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अतएव देश के अस्तित्व को चुनौती देने वाले बाहरी या भीतरी असामाजिक तत्व कानूनी शिकंजे से बचने न पाएं, इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। यही कानूनी प्रावधान बृहत्तर सामाजिक हित राज्य को भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा से जोड़ते हैं। भारत के विरुद्ध सांप्रदायिक कट्टरता फैलाने और सरकार के लिए नफरत के हालात बनाने में भारत विरोधी विदेषी ताकतें सोषल मीडिया का मनचाहा एवं गलत दुरुपयोग करती हैं, इसलिए नए कानून में देष तोड़ने की कोषिष करने वाली ताकतों पर अंकुष के लिए कठोर कानूनी प्रावधान नए कानून में हैं। अतएव स्वतंत्रता के 76 साल बाद भारतीयों को वास्तव में ऐसी प्रणाली मिल गई है, जो दंड की बजाय अधिकतम न्याय पर आधारित है।

परीक्षाएँ

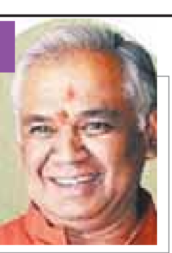

राजीव खंडेलवाल

*(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)*

# क्या नीट परीक्षा व्यापमं से भी ज्यादा 'व्यापक' होती जा रही है?

नीट पेपर लीकेज की गंभीरता को समझने के लिए इसी तरह का कांड व्यापम की गंभीरता को समझ लीजिए। याद कीजिए! वर्ष 2013 में हुआ आजाद भारत के मध्य प्रदेश का विश्व व्यापी बहुचर्चित 'व्यापम' (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) कांड जिसमें लगभग 50 से अधिक छात्रों, गवाहों, पत्रकारों, आरोपियों की 'संदिग्ध' मृत्यु, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना द्वारा हुई थी। हजारों (5288) अभियुक्तों के खिलाफ सैकड़ों अपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, जिनमें से सैंकडों आरोपी अभी भी फरार है। परंतु मामला अंतिम परिणाम तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसा ही नीट परीक्षा पेपर लीक कांड (वर्ष 2024) है, जिसके परिणाम 4 जून को आए, जिसकी चिंता राष्ट्व्यापी चर्चा का विषय बनी है। नीट परीक्षा का संचालन करने वाली संस्था एनटीए के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी भी मध्य प्रदेश के ही हैं। आईये! इस नीट पेपर कांड की कुछ परतें खोलने का प्रयास करते हैं।

**'एनटीए का गठन कब और क्यों?'**– विभिन्न राज्यों में पेपर सेट करने की विभिन्न एजेंसीज होने से होने वाली अनेक गड़बड़ियां, अनियमितताएं तथा पेपर लीकेज के रोकथाम के लिए वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एकल स्वायत्त स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने की घोषणा की थी, ताकि प्रवेश परीक्षाओं को दोषमुक्त किया जा सके। परिणाम स्वरूप 1 मार्च 2018 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) अस्तित्व में आयी।

**अभी तक के प्रमुख पेपर लीक प्रकरण** –नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के गठन के बाद से ही दुर्भाग्यवश तकरीबन हर साल परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। यानी एनटीए 'अकड़ी मकड़ी दूधमदार, नजर उतर गई पल्लेपार' कराने वाली एजेंसी मात्र बन कर रह गयी है। पिछले 5 सालों में एनटीए की लगभग 60 परीक्षाओं में से लगभग 12 परीक्षाओ में पेपर लीक या अन्य गड़बड़ियों पायी गई। साल 2019 में जेईई मेंन्स के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ जगहों पर छात्रों ने प्रश्न पत्र में देरी की भी शिकायत की थी। नीट अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। परीक्षा को कई बार स्थगित करना पड़ा था। साल 2021 में जेईई मेन्स के एग्जाम में कुछ गलत प्रश्न को लेकर भी हंगामा देखने को मिला था। 2021 में ही नीट परीक्षा में राजस्थान के भांकरोटा में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था। विभिन्न केंद्रीय, राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटीएंट्रेंस टेस्ट में साल 2022 में गड़बड़ी की शिकायतें हुई थीं। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्थान से आई थी।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर..ये देश के वो 16 राज्य हैं, जहां पिछले 5 सालों में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे लगभग 1 करोड़ 70 लाख छात्र प्रभावित हुए। यानी परीक्षा में पेपर लीक की महामारी देशभर में फैली हुई है।

**सरकार की नाक के नीचे गड़बड़ियां** – 18 जून को हुई यूजीसी-नीट की परीक्षा भी रद्द की जा चुकी थीं। तथापि कारण जनसाधारण को नहीं बताए गए हैं। एनटीए की स्थापना के 6 सालों में सिर्फ 2 बार, साल 2018 और 2023 में पेपरलीक और गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई? अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क से लेकर ओएमआर शीट व फायनल स्कोर कार्ड में अंतर, 67 उम्मीदवार को 720 में से 720 अंक, एक ही सेंटर से 6 उम्मीदवारों को नम्बर वन ऑल इंडिया रेंकिग, ग्रेस मार्क सहित 718-719 अंक संभव नहीं, सिलेबस व आंसर के हिसाब अलग-अलग आंसर गलत प्रश्नपत्र का बंटना, अंतिम तिथि 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अचानक 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन खोलना, नियत तिथि 13 जून के पूर्व ही 4 जून जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, परिणाम घोषित कर देना, आदि आदि गड़बडियां, धांधलीयां सामने आ चुकी हैं। गड़बडियों की भयानकता व व्यापकता इतनी विशाल पैमाने पर हुई है कि विभिन्न राज्यों के लगभग 20 हजार छात्रो ने उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट के विरूद्ध याचिका दायर की है। उत्तर प्रदेश के विधायक बंदीराम जो पूर्व में पेपर लीक के मामले में दो बार जेल जा चुके है, का नाम फिर से इस पेपर लीक कांड में सुर्खियों में आया है। सीबीआई ने पहली दो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां मनीष प्रकाश एवं आशुतोष की पटना से की हैं।

**नैतिक जिम्मेदारी केवल सांकेतिक**– शिक्षा मंत्री को इन अनियमितताओं व गड़बडियों को देखते हुए नैतिक जिम्मेदारी वह भी मात्र 'शब्दों' के द्वारा 'कार्य रूप' में नहीं? स्वीकार करना पड़ा। एनटीए को क्लीन चिट देने में की गई जल्दबाजी को भी स्वीकारा। मगर अब भी लगता नहीं कि 'शुतुरमुर्ग ने रेत में से सर निकाल लिया।' अंततः इस गड़बड़ी को रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति आईएसआरओ के पूर्व चेयरमेन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित की गई है। परिणाम स्वरूप एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया। उनके खिलाफ न कोई जांच नहीं बैठाई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार एक अध्यादेश ला रही है, जिसमें एक करोड रुपए तक जुर्माने एवं 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।

**राष्ट्रीय चिंता का विषय** –उपरोक्त फायदे के साथ परीक्षा लीक राष्ट्रीय चिंता एवं चिंतन का विषय होना चाहिए? जहां प्रारंभ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर में किसी भी प्रकार की गड़बडी से बिल्कुल इंकार किया था। कुछ समय बाद फिर दो जगहों पर अनियमितताओं की जानकारी बात कही। फिर प्राथमिकी दर्ज हुई। फिर अभी तक (बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात से) लगभग 40 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है। तथापि किंगपिन संजीव मुखिया अग्रिम जमानत कराने के 'कवरेज' में है। मामला अंततः सीबीआई को सौंपा गया। दूसरी तरफ 1563 ग्रेस अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए एनटीए ने पुनः परीक्षा कराई है। सरकार को संवेदनशील तंत्रों को 'लीक-प्रूफ' बनाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए विद्यमान समस्त कमियों को दूर करने की नितांत आवश्यकता है।

**असमंजस की स्थिति** –सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि उकत गड़बड़ियों के बावजूद न तो उच्चतम न्यायालय ने और न ही केन्द्रीय सरकार ने नीट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय अभी तक लिया है। अंततः यदि काउंसलिंग के बाद पेपर निरस्त किया जाता है,जिसकी पूर्ण संभावना दिख रही है, तब छात्रों का समय और अधिक बर्बाद होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा तुरंत लगातार सुनवाई न करना, काउंसलिंग पर रोक न लगाने से यह लगता है कि स्थिति को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वैसे ''व्यापक'' स्तर पर हुई गड़बड़ियों को देखते हुए नीट परीक्षा का निरस्त होना निश्चित है। फिर चाहे यह कार्य एनटीए, शिक्षा मंत्री अथवा उच्चतम न्यायालय करे।

# प्रजातांत्रिक देश का अर्थ

कटाक्ष

सुरेश रायकवार

**लेखक व्यंग्यकार हैं।**

दयारामजी की अंग्रेजी मीडियम से बारहवीं तक पढ़ी-लिखी पत्नी आजकल हिन्दी पढ़ रही है, और शायद इसीलिए हिन्दी के हर शब्द का संधि-विच्छेद भी कर रही है। सुबह-सुबह दयारामजी को चाय का प्याला पकड़ाते हुए बोली ङ्क सुनो जी! ये समाजवादी, कट्टरवादी आदि देश तो समझ आते है किन्तु प्रजातांत्रिक देश का अर्थ क्या होता है? क्या देश का हर नागरिक तांत्रिक होता है या उस देश का निर्माता कोई तांत्रिक होता है, ऐसा तो नहीं वहाँ का राजा कोई बड़ा तांत्रिक होता है या फिर वो देश केवल तंत्र-मंत्र से चलने वाला देश होता है!

बेचारे दयारामजी प्रजातांत्रिक देश के इन अर्थों को सुनकर भौचक्के रह गए, चाय पीना तो दूर, चाय का घूंट उतारना मुश्किल हो गया। किन्तु प्रश्न, चूंकि पत्नी ने किए थे, तो उत्तर तो देना ही पड़ता। पत्नी से बोले - तुम नाश्ता तैयार करो तब तक मैं तुम्हारे प्रश्नो के उत्तर ढूँढता हूँ।

दयारामजी ने पत्नी के प्रश्नो पर बड़ी गंभीरता से विचार किया और इस विचार मंथन के बाद, नाश्ते पर प्रजातांत्रिक शब्द की इस नई व्याख्या से सहमत होते हुए बोले ङ्क हाँ प्रिये! तुमने बिल्कुल ठीक कहा - प्रजातांत्रिक देश तांत्रिक ही चलाते हैं इसीलिए तो देश में, हर पाँचवें वर्ष चुनाव के बाद चमत्कारिक परिवर्तन नजर आते है। जिस तांत्रिक दल का चुनाव मंत्र चल जाता है वही देश पर शासन के लिए चुन लिया जाता है। कभी कभी इनके चुनावी मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उसकी लहर में प्रजा सम्मोहित हो जाती है किन्तु बाद के पाँच वर्ष केवल पछताती है।

यूं तो इन दलों का हर तांत्रिक, मंत्रों का ही दास होता है किन्तु चुनाव का समय, इनके लिए बड़ा ही खास होता है। हर तांत्रिक कोई ना कोई गुंडा रूपी भूत जगाता है उन्हे मदिरापान करवाता है और मुर्गों आदि का भोग लगाता है। भूतों के लिए किए गए इस अनुष्ठान की सफलता रंग लाती है और तांत्रिक को उसकी आराध्य-स्थली संसद या विधानसभा पहुंचाती है। यहाँ पहुँचते ही तांत्रिक सत्ता-देवी से विशेष शक्तियाँ प्राप्त करता है और अपनी विद्या अनुरूप मंत्री पद पाता है। अब यह मंत्री इन शक्तियों के बल से राई को पर्वत और पर्वत को राई बना सकता है यह चाहे तो चपरासी को बाबू और बाबू को अफसर बना सकता है तथा ट्रान्सफर का खेल तो ये बाएँ हाथ से खेलता है, सुबह मंत्र पढ़ता है, शाम को आपका ट्रान्सफर ऑर्डर तैयार मिलता है।

पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा - तो ये तांत्रिक ट्रान्सफर के अलावा क्या क्या करते है?

दयारामजी पत्नी को समझाते हुए बोले - मेरे ख्याल से तो ये प्रजा की भलाई को छोडकर सभी कुछ करते है, सर्वप्रथम तो चुनावी हवन में हुए खर्चे की वसूली करते है फिर पाँच वर्ष में कम से कम दस देशों की सरकारी व्यय पर, परिवार सहित यात्रा करते है। और फिर बचे हुए समय में निर्माण के दौरान ही टूट जाने वाले पुल बनवाते है, गड्ढे वाली सड़के बनवाते है, फ्री का राशन और सुविधाएं देकर नागरिकों को प्रमादी और आलसी बनाते है, जनता इनके राज में भले ही त्राहि त्राहि कर रही हो किन्तु ये अपनी उपलब्धियां ही गिनाते है। और हाँ बिना भेंट पूजा के ये किसी भी कार्य के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ते है। भेंट-पूजा की मात्रा के आधार पर ही ये निर्णय लेते है कि कार्य निष्पादन के लिए कितनी शक्ति का और कौनसा मारक मंत्र पढ़ना है।

पत्नी ने फिर प्रश्न किया - तो फिर, जो विपक्षी दल के तांत्रिक होते है वे क्या करते है?

हाँ प्रिये तुमने सही प्रश्न किया - इन तांत्रिकों को जीत तो मिलती है किन्तु सत्ता-देवी से शक्तियाँ नहीं मिलती है। सत्ता-सुख भोग रहे दल के मंत्रों को निष्प्रभावी करने के लिए ये पूरे पाँच वर्ष धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, पद-यात्रा आदि मंत्रों का जाप करते रहते है और यदि ये मंत्र प्रभावी रहे तो पाँच वर्ष के बाद इन्हे सत्ता देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वैसे तो विपक्षी तांत्रिको के ये दल एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं किन्तु सत्ता-देवी से आशीष प्राप्त करने के लिए ये गठबंधन बना कर, सत्ताधारी तांत्रिकों के विरुद्ध अपने मंत्रों से लगातार सामूहिक प्रहार करते रहते है। एक बात और, विपक्षी तांत्रिकों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग करना अपरिहार्य होता है।

इन तंत्रिकों के पास कुछ सिद्ध मंत्र होते है जिनका प्रयोग करके ये देश की सत्ता-देवी तक पहुँचते हैं। मंहगाई, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जाति-धर्म आदि इनके प्रसिद्ध मंत्र है और इनका समयानुसार प्रयोग ही प्रजातन्त्र है।

पत्नी के हिन्दी पढ़ने से दयारामजी को भी आज नया ज्ञान प्राप्त हुआ था।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

**'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।**

व्यंग्य

राजेंद्र बज

**लेखक व्यंग्यकार हैं**

# पकोड़े तलने से क्रिकेट खेलना बेहतर होगा

वैसे तो मैं क्रिकेट के मामले में एकदम ढ, ढक्कन का हूं। लेकिन श्रीमती जी की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशा करता हूं। यही कारण है कि बीती रात जब भारत के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर देश का डंका बजा दिया, उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने एक कप चाय की फरमाइश कर दी। वैसे तो निर्धारित समय से पहले उनका मेरे लिए चाय बना देना, कहीं से कहीं तक संभव नहीं होता था। लेकिन देखते ही देखते श्रीमती जी ने चाय ही नहीं अपितु उसके साथ पकोड़े भी बना दिए। यदि मैं उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी से अनजान रहता, तो बेसमय चाय के साथ पकोड़े का मिल जाना, मेरे लिए दुनिया के आठवें आश्चर्य से कम नहीं होता। खैर।

पकोड़े खाते-खाते दूर कहीं पटाखों और नगाड़ों की आवाज ने मेरे मन में उत्सुकता जगा दी कि घर से बाहर निकला जाए और झूमते-गाते क्रिकेट के दीवानों की दीवानगी का नजारा देखा जाए। आदमी को जितनी सरकारी नौकरी मिलने की खुशी नहीं होती, उससे हजार गुना खुशियां हजारों की भीड़ में बिखरी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई मालामाल हो गया हो। वरना मैं तो यह समझता था कि महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते देश के नागरिकों का जीना दुश्वार हो रहा है। बेरोजगारी के दौर में अधिकांश घर परिवारों में अपनी आरामदायक तो छोड़ो, बल्कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के भी लाले पड़ रहे हैं।

लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके आधार पर ऐसा लगा कि युवाओं को अलादीन का चिराग हाथ लग गया है। वह तो भला हो क्रिकेट के खिलाड़ियों का, जिन्होंने रोते हुओ को हंसने ही नहीं अपितु ठहाके लगाने को भी प्रेरित कर दिया। इसे लेकर मन में विचार आता है कि हजार समस्याओं की तो बस एक ही दवा है कि हमारे क्रिकेट के सितारे लगातार विश्व स्तर पर उत्कृष्ट बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए मैदान में चीते जैसी फुर्ती और हिरण जैसी चौकन्नी नजरों से मैदान में उछलती कूदती बाल को बाउंड्री पार कर सके या कि लपक सके। इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पंच से लेकर सांसद के नेतृत्व में बेरोजगारों की क्रिकेट टीम गठित कर देनी चाहिए।

वैसे जब देश के नाम क्रिकेट का कोई बड़ा तमगा मिल जाता है, तब क्रिकेट के दीवाने ही नहीं अपितु मेरे जैसा आम आदमी भी सबको खुश देखकर खुद भी खुश हो लेता है। सुखी जीवन का यह एक राज है कि आदमी दूसरों की खुशी में यदि खुश रहना सीख जाए, तो जमाने की हर चुनौतियों से पार पा सकता है। मन में एक विचार यह भी आता है कि देश-प्रदेश की सरकार यदि अपने नागरिकों की सच्चे मन से खुशियां चाहती है, तो उसे तमाम विकास कार्य और दातारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने की अपेक्षा देश-प्रदेश में क्रिकेट के महारथियों की लंबी-चौड़ी फौज तैयार करने की दिशा में अनवरत योजनाक्रियान्वित करनी चाहिए।

इन सब बातों का लब्बोलुआब यह है कि बेरोजगारों को पकोड़े तलने जैसा गैर व्यावहारिक सुझाव देने के बजाय क्रिकेट खेलने की दिशा में प्रेरित किया जाना चाहिए।

सचमुच जिंदगी का मजा आ जाएगा। दरअसल क्रिकेट ही ऐसा खेल है जिसमें धर्म, संप्रदाय, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर कहीं से कहीं तक किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता। देश की टीम हर देशवासी के लिए अजीज होती है, फिर चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी विचारधारा की पोषक हो। आमतौर पर मैं क्रिकेट के प्रति अरुचि के बावजूद एक दिवसीय मैच के अंतिम ओवरों के खेल में थोड़ी बहुत तो रुचि ले लिया करता हूं। देखता हूं कि दर्शक दीर्घा में आम और खास दोनों ही वर्ग खास तौर पर सच्ची भारतीयता का प्रदर्शन करते हैं।

शिक्षा व्यवस्था

सोनम लववंशी

वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका

# 'पेपर लीक-व्यवस्था वीक' से टूटता भरोसा

**राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे तमाम राज्य हैं। जहां की प्रादेशिक परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याएं आम बात रही हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं और एनटीए जैसा बड़ा संगठन अगर परीक्षाएं बेहतर तरीके से नहीं करवा पा रहा है तो उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाज़िमी है। वैसे भी नेट की परीक्षा केवल सरकारी खजाना भरने के अलावा ज्यादा महत्व रखता नहीं।**

पेपर का लीक होना बेहद दुखद प्रसंग है। युवाओं के साथ खेल इस तरह से खेला जा रहा है कि परीक्षार्थी अब सुनहरे सपने के बजाय आज़ादी के अमृत काल में विषपान को विवश हो रहे हैं। दुर्दांत अपराधी हैं, जो युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उस रहनुमाई व्यवस्था को लेकर क्या कहा जाए जो दावा तो आज़ादी के अमृतकाल और अच्छे दिनों का करती है? ऐसे में कहां गए उसके वो दावे और वादे, जिसकी बिसात पर सत्ता की मद में आमद होकर सियासतदानों ने एक दशक के क़रीब करोड़ों-अरबों रुपए बना लिए, लेकिन युवाओं को मिला तो सिर्फ़ खोखले वादे और पेपर लीक वाली सरकारी व्यवस्था! पेपर लीक किसी एक सरकार में उपजी कोई फौरी समस्या नहीं है, लेकिन बनी-बनाई व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाने का काम आज़ादी के अमृतकाल के नाम पर हो, तो शोक सभा व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों के नाम पर होना चाहिए। शब्दों का मायाजाल थोड़ा चुभने वाला हो सकता है। लेकिन, परीक्षा का जो भ्रमजाल बनाकर युवाओं का भविष्य, उनका वर्तमान, उनका समय और उनका परीक्षा फॉर्म के नाम पर पैसा बर्बाद किया जा रहा उससे कहीं कम है सरकारी तंत्र के लिए इन शब्दों की चुभन। दर्द जब बेइंतहा उठने लगे तो उसकी वेदना में सरकार और उसका सरकारी तंत्र दोनों बेईमानी लगता है।

वर्तमान समय का आलम कुछ यूं ही है। सरकारी तंत्र ने नेट की परीक्षा रद्द करने का एक फरमान जारी किया है। वह भी आज़ादी के अमृतकाल वाले लैटर हैड पर। अब ज़रा सोचिए आज़ादी का ये कैसा अमृत महोत्सव है? जहां युवाओं को पिलाया ज़हर का घूंट जा रहा। निःसन्देह युवाओं की वेदना, पीड़ा और रुदन किसी विष का पान करने से कम नहीं है। पहले नीट की परीक्षा में धांधली और अब नेट की परीक्षा रद्द। उसके बाद लगातार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे सीआईएसआर नेट का स्थगित होना। ये साबित करता है कि देश में सरकारी पात्रता परीक्षाओं का हाल ऐसा है, जैसे किसी मुहल्ले के स्कूल की परीक्षा। सच पूछिए तो इतनी धांधली तो राज्यस्तरीय परीक्षाओं में नहीं होती। जितना अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धांधली हो रही है।

नीट परीक्षा का आलम यह हुआ कि औने-पौने हिसाब से नंबर बांट दिया गया। नीट परीक्षा में नंबर इस तरह से प्रसाद में बांटे गए जैसे किसी का कथा के बाद प्रसाद हो। वैसे महंगाई के इस दौर में प्रसाद भी सोच-समझकर बांटा और बनाया जाता है, लेकिन एक हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था है। जहां सोच-समझ कर लगता है कोई काम नहीं हो रहा। परीक्षा फॉर्म के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपए बार-बार वसूले जाते हैं। साल-दो साल के भीतर परीक्षा फॉर्म के लिए लगने वाली फ़ीस बढ़ा दी जाती है, लेकिन युवाओं के जीवन में परीक्षा के बाद कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तभी तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है और मजबूत और सुरक्षित हाथों में जिसके देश की सरकार है। वो नेट जैसी परीक्षा को रद्द करवाकर जांच सीबीआई को सौंपकर ही भारत माता भाग्य विधाता की धुन में मदमस्त है।

राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे तमाम राज्य हैं। जहां की प्रादेशिक परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याएं आम बात रही हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं और एनटीए जैसा बड़ा संगठन अगर परीक्षाएं बेहतर तरीके से नहीं करवा पा रहा है तो उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाज़िमी है। वैसे भी नेट की परीक्षा केवल सरकारी खजाना भरने के अलावा ज्यादा महत्व रखता नहीं। क्योंकि, हर छह महीने में 10 लाख के क़रीब अभियार्थी फॉर्म भरते हैं और परीक्षा के बाद का लब्बोलुआब सिर्फ़ एक सर्टिफिकेट होता है। जिसके बाद न तो पीएचडी में एडमिशन मिलता और न ही अस्सिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति। ऐसे में रहनुमाई व्यवस्था और उनके सिपह-सालारों से सवाल यही है कि क्या उनके बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होता तो उनके आंखों का पानी मरा रह पाता!

सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन जवाब देने से अब सत्ता और सत्ताधीश डरते नहीं या देना चाहते नहीं हैं। तभी तो कई मर्तबा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठता है। वैसे अब बात सिर्फ़ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, जीवन जीने की स्वतंत्रता और जीवन में सफल होने की चुनौती बहुत बड़ी हो चली है, क्योंकि सरकारी नौकरी ही आज की सामाजिक व्यवस्था में सर्वस्वीकार्य है और उसके लिए आयोजित परीक्षाएं ही धांधली की शिकार है। सियासतदां, युवाओं का दर्द समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके बच्चें या तो बड़े राजनीतिक पद पर है या बिज़नेस में हैं। वरना विदेश में नेताजी की कमाई से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि 'जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई!'

संकल्प

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

# 'मन की बात' की पुनः उपस्थिति

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परहित के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से एक संवाद मंच 'मन की बात' स्थापित किया, जहाँ भारतीय आमजन के उत्तरोत्तर विकास व विस्तार की बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने और सपने बुनने की अब भारतीय जनमानस को आदत पड़ चुकी है। चुनाव आने पर जब-जब इसके प्रसारण को बंद किया गया, लोग निराश हुए। वह प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनना चाहते हैं। आम जनमानस से भी कोई अब पूछ ले तो यही कहेगा कि जब मन की बात का प्रसारण कुछ समय के लिए रुक जाता है तो खालीपन लगता है। जैसे कुछ अधूरा सा हो, ऐसा एहसास होता है।

मन की बात के 100 एपीसोड पूर्ण होने पर जब मुझे आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण हेतु रूपक 'जन-जन की बात मन की बात' लिखने का अवसर मिला। मुझे सम्पूर्ण भारत से मन की बात पर प्रतिक्रिया सुनने-समझने को मिली। जब जन-जन की भावनाओं में, अंतस्थल में मन की बात के लिए कुतूहल, उत्साह, आशा व विश्वास का आंकलन किया तो यह लगा की 'मन की बात' कोई आम श्रृंखला नहीं है अपितु सही मायने में यह लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। बीते रविवार को एक अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' से एक बार पुनः जुड़े। मन की बात की भी एक सद-इच्छा है कि भारतीय जनमानस परिपक्व मन से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबध्द हो।

अब तक मन की बात में व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री ने उन बुनियादी विषयों को उठाया है जिससे सर्वजन का भला हो। भारत की उपलब्धियों को बताया। स्त्रियों की सफलता की कहानी भी उन्होंने बताई। अंग दान, शिक्षा दान, रक्त दान व परोपकार की अलख जगाने वाली मन की बात में योग, जीवनचर्या, कला, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, श्रम, संस्कार, पर्यावरणीय सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, सैन्यजन की सेवा, कर्तव्यपरायणता और मेलजोल, सद्भावना, सहिष्णु समाज की रचना, विरासत का संरक्षण और लोक की बात सभी क्षेत्रों पर गंभीर, गहन अध्ययन व शोध से उस तत्व को प्रधानमंत्री ने आमजन को परोसा है जिससे समाज का भी भला हो और देश भी आगे बढ़े। मन की बात की निरंतरता तो इसीलिए समाज की मांग बन गयी है। उसके जीवन का हिस्सा बन गयी है। समाज ने इस मन की बात में संजीवनी खोजकर अपने जीवन को जब तरसना शुरू किया, तो कैसे न उनके लिए इतनी प्रिय हो मन की बात? देश की विविधता का एक बार ख्याल करें। देश की अभिरुचियों का ध्यान करें तो

कितनी विविधतापूर्ण हमारा समाज है लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण की तरह सोच के एकीकरण को स्थापित करती मन की बात ने सब के मन-मस्तिष्क को अपना बनाया।

आज पृथ्वी की भलाई के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हमारे श्रेष्ठ विचार आवश्यक हैं। दुनिया तो बड़े पैमाने पर तनाव से भी गुजर रही है। बहुतेरी चुनौतियाँ हैं। कहते हैं इसके लिए दृष्टि व दृष्टिकोण के साथ नेतृत्वकर्ता की इच्छाशक्ति बहुत मायने रखती है। जिन देशों में अराजक स्थितियां हैं वहां की जनता सुखी नहीं है। भारत के लिए यह वरदान है की हमारे देश का नेतृत्व भारतीय मानस के अनुकूल विचार कर रहा है। मन की बात इसकी एक मिसाल है। राजनीति से दूर प्रतिभागिता की लहर पैदा करने वाली संवाद की एक असीम संभावना लिए 'मन की बात' से भारत को जो बल मिल रहा है, उसके बारे में अन्य देश केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत के लिए अच्छी बात है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व सोच की वजह से जन-जन उन संभावनाओं के लिए या तो स्वप्न देख रहा है या उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। मन की बात 30 जून को जब एक बार पुनः प्रसारण के साथ अपने भारतीय जनमानस को जोड़ेगी तो कुछ नए गान भारत का अभिषेक करेंगे। भारत की सभ्यता व संस्कृति को समृद्धि प्रदान करेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनायेंगे क्योंकि हमेशा की तरह मन की बात में निःसंदेह प्रधानमंत्री भारत की जनता की भले कृतज्ञता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने पर ज्ञापित करेंगे लेकिन वे यह भी भारतीय मन में स्थापित करेंगे कि हमारे सामने नए भविष्य के द्वार अब खुल चुके हैं और हमें प्रकृति, जन और मन के बीच एक ऐसे सेतु को स्थापित करना है जिससे हमारी आने वाली पीढियां हम पर गर्व करें।

भारत की जन-सरोकारी अभिव्यक्ति की यह गाथा अपने विगत संवाद से जिन सफलताओं को प्राप्त की है, उसमें मौलिकता जनता की मांग होगी। प्रधान-मंत्री स्वप्नदर्शी हैं, श्रेष्ठ कार्यों को लक्ष्य तक ले जाने वाले व्यक्तित्व हैं तो वे भारत की गरिमा को गौरव-गाथा के रूप में अंकित करेंगे भी। भारत के सुनहरे व उज्जवल पक्ष के नए अध्यायों में निरूपित होने वाली 'मन की बात' से एक श्रेष्ठ भारत की रचना होगी, इसका भारतीय लोगों में विश्वास भी है। जो भी हो, एक बार पुनः भारत की जनता के बीच प्रधानमंत्री की 'मन की बात' के माध्यम से उपस्थिति जब बनने जा रही है। इस सुखद क्षण से वही प्रतिफल आएंगे जो हमारे मन में बातें प्रतिष्ठित होंगी। प्रधानमंत्री ने देश को सर्वोपरि माना। जन-जन की भावनाओं को सम्मान दिया। इस निरंतरता की अपेक्षा भारत की जनता करती है। पृथ्वी के अन्य भूभाग की जनता ऐसी भावना को मन में ला भी नहीं सकती। फिलहाल, आशाओं से भरे भारत में मन की बात से जो उम्मीदें हैं वह सर्वे भवन्तु सुखिनः की व्याप्ति पर आधारित हैं जिसमें सबका कल्याण है। भारत की जनता के बीच 'मन की बात' की कीमत इसलिए अप्रतिम है।

दृष्टिकोण

विवेक कुमार मिश्र

लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

# स्वयं के संकल्प से शुरू होता है जीत का मुहावरा

जब जीत जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, जब जीतना लक्ष्य होता है, जब जीत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता तब जीत होती है। इस जीत को जीना पड़ता है। जीने का जरिया ही जीत में छिपा होता है और इस तरह जब जी रहे होते हैं तो समय असमय बस एक ही सवाल मन पूछता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। यह सवाल अकेले का भी नहीं होता न ही जीत अकेले की होती है...जीत के मार्ग में चले हर कदम की जीत होती है और हर कदम को महत्व देने का काम ही नायक का होता है। जीत हमारे जज्बे में होती है। हमारे भीतर ही होती है। जीत बैठी होती है और हम सब पता नहीं कहां कहां भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं जैसे कि वह बाहर हो , जीत के लिए भीतर के साहस को साथ लेकर चलना पड़ता है। कोई भी जीत क्यों न हो वह संघर्ष के रास्ते आती है। जो संघर्ष में नहीं है जो संसार के उतार चढ़ाव नहीं देख रहा है, जो यहां से वहां की कठिनतम यात्रा को जी नहीं रहा उसके लिए जीत का कोई भी अर्थ नही होता। वह एक किनारे पर पड़ा होता है। वह न यात्रा में होता न संघर्ष में होता न जीत में होता पर किनारे पर यूं ही पड़ा होता है।

यह संसार की हर कहानी का एक सच है कि कहानी कहीं से शुरू हो सकती है पर कहीं पर खत्म नहीं होती , न ही आपकी इच्छानुसार खत्म होती। कहानी तो कहानी की तरह जीवन संघर्षों में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हम सबकी दुनिया होती। किसी एक भर की दुनिया से कहानी , साहित्य और जीवन संस्कृति का काम नहीं चलता न ही जीवन के भाव केंद्र किसी एक के अनुसार चलते पर कहानी के विस्तार में, जीवन की जीत में सब शामिल हो जाते हैं। जीत का मुहावरा ही इस बात से शुरु होता है कि 'जीत जायेंगे' यह जीत जाना और जीत जायेंगे का भाव ही जिंदगी में जीत दर्ज कराता है। आधी लड़ाई जीत के भाव में होती है वह हमारे भीतर ही होती है। कहीं बाहर नहीं जीतना है, सबसे पहले खुद को जीतना होता है अपने आप पर विजय पानी होती है। अपनी कमजोरियों से लड़ना होता है यह आसान नहीं होता पर लड़ना पड़ता है जो खुद पर जीत दर्ज करता है वहीं एक समय के बाद संसार में बाहर जीत दर्ज कराता है और दुनिया देखती रहती है कि हां यहां है जीत का नुस्खा यहां से जीत की किताब लिखी जाती है और को राह यहीं से मिलती है। जब यह अखंड विश्वास होता है कि जीत जायेंगे, इस परीक्षा को निकाल लेंगे, इस मंजिल को पार कर जायेंगे या इस पहाड़ को फतह कर लेंगे या कोई भी शिखर क्यों न हो वह मेरे साहस से बड़ा नहीं है। जब इस तरह से हम सोचते हैं तो कोई भी हमारे कदम रोक नहीं सकता। जब इस तरह का भाव भीतर भरा होता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, तब तो बस यही लगता है कि यह कार्य हम कर लेंगे और यहीं पर आकर यह कहना भी उचित लगता है कि मनुष्य के आगे कोई भी संसार, कोई भी समय कोई भी दुनिया मुश्किल नहीं है वह कुछ भी कर सकता है। किसी भी असंभव जैसे शब्द को संभव बना सकता है। चुनौतियां, हालात, कठिनाइयां उसके यहां से गायब हो जाते हैं। उसके शब्दकोश में बहाना नहीं होता न ही आगे पीछे देख लेने की इच्छा। वह तो इसी समय में इसी वर्तमान में जीना और जज्बे के साथ, साहस के साथ और जीत के भाव को लेकर जीने की ऐसी कोशिश करता है कि जिस पर अन्य भी अपने जीवन को जीकर कस सकें।

जीत जाने की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए हम कदम किस स्तर पर बढ़ाते हैं। हमारे भीतर जीत जाने का विश्वास कितना है और उस विश्वास की रक्षा के लिए कितना कुछ करते हैं। जीत का भाव, जीत के जज्बे को लेकर ही एक खिलाड़ी चलता है और यह सारा भाव खेल के मैदान में देखने को मिलता है। संघर्ष की भूमि में , वास्तविक संसार में ही यह जज्बा होता है। आप संसार से परे जाकर अमूर्त रूप में जीत की कल्पना नहीं कर सकते इस तरह कोई अर्थ भी नहीं बनता है। जब हम जीतते हैं तो साहस का मूल्य, संघर्ष की क्षमता, कार्य कुशलता, तकनीकी दक्षता, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश एक साथ प्रकाशित होती है।

कई बार यह सुनने में आता है कि क्या हो गया वह जीत गया तो, जीतने का भी संयोग होता है, बस जीत गया तो जीत गया। पर यहां यह कहा जाना उचित लगता है कि संयोग से एक बार जीत सकते हैं यह एक तरह का जिंदगी में मिले अवसर की तरह होता है पर जीतने का जज्बा रखना , जीत को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाना और इसलिए खेलना की हां मुझे जीतना है यह केवल खेल के मैदान पर ही लागू नहीं होता वल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसी भाव और जज्बे से जब चलते हैं तो जीत का संकल्प हमारे साथ चलता है। हमें जीत के लिए चलना है, हमें अपने लक्ष्य के कदम बढ़ाना है और हर हाल में अपना श्रेष्ठतम प्रस्तुत करना है जब इस तरह कदम बढ़ाते हैं तो आप से आप कदम आगे बढ़ते हैं और इस तरह के कदम कभी अकेले नहीं होते उनके साथ लाखों मन चलते हैं उन कदमों में लाखों की जान होती है। जब जीत के लिए चलते हैं तो खिलाड़ी के मजबूत इरादे और विराट साहस को देखना पड़ता है तब बहुत ही सधे ढ़ंग से चलना होता है। आपको कहीं भी रुकना नहीं होता न ही कोई चूक करनी होती है क्योंकि यहां एक भी चूक भारी पड़ सकती है। आपकों यहां कार्य करना होता है, जहां कोई नहीं कर सकता वहां आपको अपने जज्बे के बल पर कुछ अतिरिक्त करना होता है। असंभव तारे को पकड़ लाने की जब क्षमता होती है तो आपके भीतर असाधारण व्यक्तित्व और नायकत्व की भूमिका जन्म लेती है।

वक्रोक्ति

संतोष श्रीवास्तव

*लेखिका व्यंग्यकार हैं।*

# सरकार बदलते देर नहीं लगती बंधु

शाम को ही मित्र अनोखे का फोन आया। वैसे अच्छेलाल अपनी शाम किसी को नहीं देते। वे मध्यवर्गीय समाज के हैं तो क्या हुआ लेकिन इस वक्त वह अपने को किसी राजा से कम नहीं समझते। आरामदायक सोफे पर बैठकर मदिरापान करना उनकी शाम का विशेष शगल है। पत्नी टमाटर प्याज हरी मिर्च का खूब तीखा सलाद बनाकर रख जाती हैं। कमरे के पर्दे खींच देती हैं। माने कि घर के किसी भी सदस्य का प्रवेश निषेध। अच्छेलाल के लिए यह वक्त यह सोचने का नहीं होता कि उन्होंने दिनभर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए क्या-क्या पापड़ बेले हैं।वे तो सुरा सुंदरी की बाहों में परम आनंद की नदिया में डुबकी मारते हैं।

पत्नी उनकी इस परमानंद की स्थिति में जरा भी बाधक नहीं होती। बल्कि उनके लिए पूरा माहौल रच देती हैं। पहला घूंट पीते ही उन्हें पत्नी पत्नी नहीं बल्कि प्रियतमा नजर आने लगती है और अंतिम घूंट तक आते-आते वे अपनी कुंठाओं से घिर जाते हैं। जीवन में जो करना चाहा वह नहीं कर सके, बस यही मलाल उन्हें जीने नहीं देता।

शाम ने दबे पांव अच्छेलाल के कमरे में प्रवेश कर लिया था।अभी उन्होंने पहला घूंट हलक में उतार कर हरी मिर्च जीभ पर धरी ही थी कि फोन की सुरीली तान रमैया वस्तावैया गीत से मुखर हो उठी। गाना इतना रोमांटिक था कि अच्छेलाल की आंखें परमानंद में डूब गई। वे स्वयं को राजकपूर समझने लगे और कॉलेज के दिनों में जिससे एक तरफा प्यार करते थे और जो उन्हें घास भी न डालती थी उसे नरगिस।

दोबारा फिर फोन ने रमैया वस्तावैया की तान छेड़ी। अब की उठाना पड़ा फोन उन्हें।उधर से आवाज थी-

यार कल पलाश रेस्टोरेंट में शाम को मिलो आकर। तुम्हें फिल्म निर्माता बासु से मिलवाता हूं। वह अपनी फिल्म की पटकथा के लिए लेखक ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। अच्छा पेमेंट करेंगे।

अच्छेलाल को खुश होना चाहिए था पर वे थोड़े अनमने हो गए - यार अनोखे, दोपहरी में मिलो न, तुम्हें तो पता है मैं अपनी शाम यमराज तक को देने के पक्ष में नहीं हूं।

दोपहरी को कहीं फिल्म वाले होश में रहते हैं।उनकी जिंदगी के हसीन लम्हे, सांठ गांठ ,योजना , कुयोजना सब शाम बल्कि यूं कहो रात को ही शुरू होती है। तुम तो 8 बजे आ जाना। गोल्डन चांस है, चूकना मत।

कहते हुए अनोखे ने फोन कट कर दिया। चलो ठीक है जाएंगे। जब से पड़ोसन के कान में कुंदन के झुमके देखे हैं तब से वैसे ही झुमके खरीद देने की रट लगाए है पत्नी।पत्नी को खुश करने में अगर एक शाम शहीद करनी पड़े तो कर लेंगे।

उन्होंने शहीदाना अंदाज में पैग खत्म किया और पत्नी को खाना लगाने की गुहार लगाते डाइनिंग रूम में आ गए।

दूसरी शाम वे पहुंच गए पलाश रेस्टोरेंट। अनोखे रेस्टोरेंट की सीढ़ियों पर ही मिल गया। कोने वाला समंदर की ओर खुलने वाली खिड़की वाला टेबल बुक था बासु के नाम।दोनों बैठकर समुद्र की नमकीन हवाओं से कलेजा तर करते हुए इंतजार करने लगे। 8 के 8=30 बज गए। सुरा की तलब ने बेकरार कर दिया अच्छेलाल को। अनोखे समझाता रहा- यार यह फिल्म वाले हैं, इंतजार करवाना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है।इसी से यह तृप्त होते हैं। बाकी तो ऊपर वाले की माया है।

परफ्यूम की तेज खुशबू उड़ाते बासु ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। अनोखे उनकी अगवानी में लपका। परिचय कराया- अच्छेलाल, पटकथा लेखक।÷ बासु कुर्सी पर ठसके से विराजमान हुए। कुछ इस अदा से कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। बैरा पानी ले आया। अनोखे ने आर्डर दिया तीन काली कॉफी और फिर नो डिस्टरबेंस।

यस सर। बैरे की कहां मजाल कि ऑर्डर पर आधा झुक कर बंदगी न करे।

बासु साहब हैं। इसी टेबल पर उनकी सुपरहिट फिल्में डिस्कस हुई है।

तो आप लिखेंगे हमारी कहानी पर पटकथा। आपका नाम बड़ा कैची है दर्शकों को एट्रैक्ट करेगा।

अच्छेलाल ने खींसे निपोरी-जी यह नाम हमारी बुआ ने रखा है।आप चाहे तो बदल दें। फिल्मों में नाम तो बदले जाते हैं।

नहीं नाम परफेक्ट है। हमने कहा न कैची है।

बासु दुबले पतले सांवले रंग के गंजी चांद पर इक्का दुक्का बाल गुजरे जमाने में अपनी लहलहाती फसल के सबूत थे।लेकिन लगे रूआबदार वे।कॉफी आ गई थी। चुस्कियां भरी जाने लगीं और बासु अपनी कहानी मुनिया सुनाने लगे।

अच्छेलाल को मुनिया की कहानी में कहीं भी कोई खास बात नहीं लगी।गांव की आम लड़की। पढ़ने की ललक। घर में चौका चूल्हा ही तो संभालेगी की हिदायत .....देखिए, अच्छे लाल जी, आपको मुनिया की पढ़ाई की इसी ललक को फिल्म में फोकस करना है।

बासु ने टाइप किए हुए 10 पन्नों की कहानी अच्छेलाल को थमा दी। अनोखे फुसफुसाया- मिस्टर बासु छेड़छाड़ ,बलात्कार, खून, मारपीट, प्रेम कुछ भी नहीं होगा क्या पटकथा में?

बासु मुस्कुराया -नहीं अनोखे जी, हम कला फिल्म चाहते हैं। लो बजट की और अपीलिंग।हमारी मुनिया समाज के लिए मिसाल बनेगी और हां आप टॉयलेट पर ज्यादा फोकस करना।

टॉयलेट पर ?अच्छेलाल चकित थे।

मुनिया गांव की है तो क्या हुआ।अब वह लोटा लेकर दिशा मैदान के लिए जंगल तो नहीं जाएगी न। गांव के सरपंच चंदा लेकर औरतों के लिए उनके आंगन में ही टॉयलेट बनवाएंगे फिल्म में। मौजूदा सरकार का यही तो वादा है। घर-घर टॉयलेट।

अब महंगाई बढ़ रही है तो बढ़े। महंगाई पर क्या जोर। लेकिन टॉयलेट जरूर अंगने में होना चाहिए।

कॉफी और कहानी एक साथ खत्म हुई। बासु ने 10 हजार की गड्डी अच्छेलाल को देते हुए कॉन्टेक्ट लैटर पर हस्ताक्षर करवाए। अच्छेलाल और अनोखे बासु को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। उन्होंने कार में बैठते हुए कहा-

समय सीमा में काम कर डालना बंधु ,सरकार बदलते देर नहीं लगती।

# जांच से मुक्त हुए मालवाहक वाहन, भ्रष्टाचार बैरियर बंद

एस. द्विवेदी

बैतूल। भ्रष्टाचार की पर्याय बनी अंतरराज्यीय सीमाओं पर बनी परिवहन जांच चौकियों के रात 12 बजे से बंद कर दिए जाने से खास तौर पर भारवाहक वाहन चालकों और बड़े यात्री वाहन के चालकों ने राहत की सांस ली है। हालाकि उन्हें अब भी संशय है कि आगे क्या व्यवस्थाएं होंगी और उनमें किस तरह के बदलाव होंगे। वे इसे मानव रहित किए जाने की हिमायत कर रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार के परिवहन जांच चोकियों को खत्म करते ही बैतूल जिले की महाराष्ट्र सीमा पर काम कर रहे चार प्रमुख जांच नाकों पर अब ताला पड़ गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब इन मार्गों से गुजरने वाले भारवाहक और यात्री वाहन फर्राटे भरते निकल रहे हैं। पहले इन वाहनों को यहां कागजात की जांच से लेकर वजन और अन्य मापदंडों की जांच कराना होता था। लेकिन सरकार ने रात 12 बजे से इसे बंद कर दिया है। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जिलाध्यक्ष सूरज दुबे के मुताबिक पहले भी प्रदेश में 56 प्वाइंट में वसूली होती थी। नई व्यवस्था में अब ज्यादा परेशानी होती है या कम यह समय ही बताएगा। वैसे इस व्यवस्था को मानव रहित बनाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजू राठौर कहते हैं कि फिलहाल तो इन चेक पोस्ट को बंद किए जाने से फौरी राहत है। गाड़ी आ रही, जा रही पर आगे क्या होगा। इस पर संशय है। बताया जा रहा है कि अब होम गार्ड सैनिक तैनात किए जाएंगे। मतलब पैटर्न वही पुराना रहेगा।

**बैतूल में थे चार बैरियर-** बैतूल जिले में महाराष्ट्र स्थित अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन विभाग ने चार चेक पोस्ट बनाए हुए थे। यहां सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ससुंद्रा में बनाया गया था। जहां परिवहन, वाणिज्य, मंडी और वन विभाग के कर्मचारी बैठकर आने-जाने वाले वाहनों के कागजात और अन्य जांच करते थे। मुख्य तौर पर यहां पर परिवहन विभाग के कर्मचारी वाहनों के दस्तावेज और उनके ओवरलोड होने की जांच करते थे। ससुंद्रा में 5 फरवरी 2011 को यह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया था। इसके अलावा जिले में महाराष्ट्र सीमा पर गुदगांव और प्रभात पट्टन में भी चेक पोस्ट बनाए गए थे। जबकि नागपुर मार्ग पर चिखली में एक जांच चौकी स्थापित की गई थी। यहां से आने-जाने वाले भार वाहक वाहनों और यात्री वाहनों की जांच की जाती थी। ससुंद्रा में बनाए गए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग ने निरीक्षक समेत करीब 13 कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ था। जबकि यहां अल्ट्रा वैक्स नाम की एक कंपनी को भार वाहक वाहनों की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कंपनी के कर्मचारी यहां कागजात और वाहनों के लोड की जांच करते थे।

### नवीन बनेगी व्यवस्था-

नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक पाइंट बनाए जाएंगे। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जांच की जाएगी। सरकार ने रविवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, प्रदेश में संचालित आरटीओ चेक पोस्ट पर लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद रविवार को परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है।

### कर्मचारी असमंजस में-

फिलहाल सरकार द्वारा बंद की गई पुरानी व्यवस्था से निजी कंपनी के कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। जबकि चेक पोस्ट पर तैनात परिवहन विभाग के कर्मचारी असमंजस में हैं कि उन्हें अब आखिर क्या करना है। एक कर्मचारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि जिस तरह कम स्टाफ में भी इन चेक पोस्ट पर काम निपटा लिए जाते थे। अब सड़क पर ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर जल्दी अमला तैयार होता है, भर्ती की जाती है तो ठीक, वरना कम स्टाफ में रोड पर काम नहीं कर सकेंगे।

## नाली से पानी निकासी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, कुल्हाड़ी से हमला कर महिला की कर दी हत्या

**बैतूल।** बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सेलगांव में रविवार को नाली से पानी निकासी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस विवाद में लाठी और कुल्हाड़ी जमकर चली। विवाद में तीन लोग जख्मी हो गए थे। जिसमें से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतिका महिला का पति और सांस गंभीर रूप से घायल है। पति की हालत नाजुक होने के कारण उसे निजी अस्पताल भर्ती किया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि संतोष उईके और किशन उईके के बीच नाली से पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस विवाद में चम्पा उईके (40) और पति संतोष उईके तथा सास सोमता बाई उईके को कुल्हाड़ी लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को उपचार के लिए रविवार शाम को जिला अस्पताल लाया गया। गंभीर घायल चम्पा बाई की जिला अस्पताल में उपचार चल रहा था, जिसे उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। भोपाल ले जाते समय रास्ते में भौंरा के पास महिला की मौत हो गई। मृतिका के पति की हालत गंभीर होने पर उसे एक निजी अस्पताल भर्ती किया है। सास सोमती बाई का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में किशन धुर्वे और उसके बेटे विजय धुर्वे ने चम्पा बाई और उसके पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसे गंभीर चोट आई है। महिला चम्पाबाई की हालत इतनी नाजूक बनी थी कि उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी श्री डहेरिया ने बताया कि इस मामले में किशन धुर्वे और विजय धुर्वे के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। इधर मृतिका का सोमवार सुबह जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

## ग्राम जामली में बच्चों की सुरक्षा पर संकट खुले कुएँ से संभावित दुर्घटनाओं का खतरा

**ग्रामीणों की शिकायत पर भी नहीं हुई कोई कार्यवाही, प्रशासनिक लापरवाही से बढ़ी चिंता**

**बैतूल।** चिचोली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामली में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, एवं आंगनवाडी के पास एक खुला कुआं बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। स्कूल और आंगनवाडी के पास खेलते बच्चों के लिए यह कुआं कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पहले भी की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीण गोविन्द पंदराम ने पहले सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका शिकायत क्रमांक 26626255 है। शिकायत में उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत आलमपुर के सरपंच, सचिव एवं उच्च अधिकारियों ने दबाव बनाकर शिकायत बंद करा दी और अब तक इस अनुपयोगी कुएँ को बंद नहीं किया गया है। इस वजह से ग्रामीणों में असंतोष और चिंता बढ़ती जा रही है। ग्राम जामली में पहले भी इसी प्रकार की एक दुर्घटना हो चुकी है, जो प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाती है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो सालों से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे इस मामले की जांच कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे जल्द से जल्द इस खुले कुएँ को बंद करें। ग्रामीणों ने आगाह किया है कि यदि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए शासन-प्रशासन जिम्मेदार होगा।

### नये कानून का किया जा रहा प्रचार प्रसार,

## जिले के सभी थाना प्रभारियों ने दी नए कानून की जानकारी

**बैतूल ।** नवीन अपराध अधिनियम 2023 के आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने के संबंध में जिलें के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक निश्छल एन झारिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के मार्गदर्शन मे सभी पुलिस थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए गए, जिसमे उपस्थित लोगों को नया भारत- नया विधान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसके साथ ही पुराने कानून एवं नए कानून में क्या अंतर है समझाया गया। इस उपलक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी द्वारा उपस्थित गणमान्य नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

## थाना गंज पुलिस ने नवीन कानून बीएनएस के तहत बैतूल जिले में दर्ज की प्रथम एफआईआर

**बैतूल।** आज 01/07/24 को फरियादी शंकर पवार पिता गिरधारी पंवार उम्र 58 साल नि0 पटवारी कॉलोनी गंज बैतूल ने थाना उपस्थित आकर रिर्पोट किया कि मेरे बडे लडके हर्षित पवार ने आज सुबह मोबाइल चार्जिंग की बात को लेकर मेरे तथा छोटे लडके पुलकित के साथ गाली गलौजकर मारपीट कर जान से मारने कि धमकी दिया है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गंज में आरोपी हर्षित पंवार के विरूध्द अपराध कं 255/24 धारा 296,115,351 (2) भारतीय न्याय संहिता (ब्नहस्) 2023 के अतंगर्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो नये कानून के तहत थाना गंज पुलिस ने बैतूल जिले में प्रथम एफआईआर दर्ज की गई। प्रथम एफआईआर दर्ज करते समय थाना प्रभारी गंज निरी0 रविकान्त डहेरिया, उनि अजय रघुवंशी, आर मनोज, आर देवेन्द्र व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा ।

## जिला सैनिक कल्याण अधिकारी 3 जुलाई को सारणी दौरे पर

**बैतूल।** कैप्टन (आई.एन.) श्री सुमीत सिंह (से.नि.) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी 3 जुलाई 2024 को सारणी दौरे पर रहेगे। इस दौरान श्री सिंह सुबह 10.30 बजे से 11 बजे तक नगर पालिका के सभाकक्ष में भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने घोड़ाडोंगरी, सारणी में निवासरत सभी भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों की पत्नियों से यथा समय उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

## हिट एंड रन मामलों के निपटारे के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता समिति गठित

**बैतूल।** भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की गई है। हिट एंड रन प्रकरणों में आरोपी अज्ञात होता है। इस योजना के अंतर्गत मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से पीड़ित को 50 हजार रुपए एवं मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर के हस्ताक्षर से इस आशय के आदेश में हिट एंड रन के प्रकरणों में दावों को निपटाने के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष दावा निपटान आयुक्त के रूप में कलेक्टर होंगे। जांच अधिकारी क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार होंगे जो प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से समिति के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत करेंगे। समिति सदस्य के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, सड़क सुरक्षा से जुड़ा स्वैच्छिक संगठन का सदस्य या आम प्रतिनिधि एवं सामान्य बीमा काउंसिल द्वारा नामांकन अधिकारी या भारतीय जीवन बीमा निगम का जिला प्रबंधक मनोनित किए गए है।

# जन परिषद का 35 वां वार्षिक समारोह आयोजित

**जनपरिषद अवार्ड से सम्मानित हुए उपसंचालक जनसंपर्क मुकेश दुबे एवं वरिष्ठ पत्रकार केपी अग्निहोत्री**

### जनपरिषद स्मारिका प्रगति का हुआ विमोचन

**बैतूल।** अग्रणी संस्था जनपरिषद के 35वा वार्षिक समारोह रविवार को स्टेट म्यूजियम श्यामला हिल्स भोपाल में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि शुक्ला, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा, पूर्व डीजीपी डीपी खन्ना, पूर्व डीजीपी एन के त्रिपाठी, पूर्व आईएएस सर्वश्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, एस के मिश्रा, मनीष श्रीवास्तव, जी पी श्रीवास्तव, आईएफएस अखिलेश अर्गल, मिस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी आशिता कोचर, मिसेज यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी प्रगति सेठ एवं मिसेज वर्ल्ड वाइड भूमिका सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा जन परिषद स्मारिका प्रगति का विमोचन किया गया।

### जनपरिषद अवार्ड से मुकेश दुबे तथा बैतूल बाजार को बेस्ट चैप्टर अवार्ड सम्मान

उपसंचालक जनसंपर्क कार्यालय बैतूल मुकेश दुबे का अतिथियों द्वारा जन परिषद के अवार्ड –लक्ष्मी रायकवार सम्मान– से सम्मानित किया गया। वही समाजसेवा के क्षेत्र में विशेश योगदान के लिए बेस्ट चैप्टर अवार्ड की श्रृंखला में बैतूल जिले के बैतूलबाजार चैप्टर को बेस्ट चैप्टर अवार्ड प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बैतूल जिले से अरुण किलेदार, विजय दीक्षित, महेंद्र गुड्डा वर्मा, संजय द्विवेदी, संतोष राठौर, भूपेंद्र राठौर, अजय पवार, कपिल डांगे, केपी अग्निहोत्री, चंद्रशेखर यादव आदि उपस्थित थे। जन परिषद के रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर समाजसेवा, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, खेल, पत्रकारिता, कृषि आदि क्षेत्रों के उपलब्धि प्राप्त व्यक्तित्वों को जनपरिषद अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा समारोह में तीन दशकों की झलकियों के साथ संगीतमय सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई।।

### वे रोते–रोते वृक्षारोपण कर रहे थे

अतिथियों द्वारा जनपरिषद के –मा प्रभादेवी सम्मान– अवार्ड से समाजसेवा के क्षेत्र में विशेश योगदान के लिए भोउरा निवासी वरिष्ठ पत्रकार केपी अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया। समारोह में शामिल के.पी. अग्निहोत्री को सम्मानित करते हुए बताया गया कि जन परिषद ने पर्यावरण की दृष्टि से सभी 210 चैप्टर्स को आव्हान किया गया था कि सभी चैप्टर्स अपने–अपने क्षेत्र में यथासंभव वृक्षारोपण करें ।संयोग से उन्ही दिनों भोरा निवासी वरिष्ठ पत्रकार केपी अग्निहोत्री के सगे भाई का निधन हो गया, इसके बाबजूद उन्होंने उस समय जितने लोग उनके यहां संवेदना प्रगट करने आए, सबको एक–एक पोधा भेंट किया और स्वयं वृक्षारोपण भी किया । वे भाई की याद में रोते जा रहे थे और जन परिषद के आव्हान पर पौधों को रोपित कर रहे थे । संचालक ने कहा कि शायद ये दुनिया का प्रथम पौधा होगा, जिसे पानी से नही, बल्कि आंसुओं से सींचा गया।

## दिलीप इवने संभागीय अध्यक्ष नियुक्त

**बैतूल।** स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ नर्मदापुरम संभागीय अध्यक्ष के पद पर दिलीप इवने बायोकेमिस्ट जिला चिकित्सालय को मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह कौरव ने की है। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ का संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर श्री इवने को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रविकांत उईके, सिविल सर्जन डॉ.अशोक बारंगा, पैथालॉजिस्ट डॉ.डब्ल्यूए नागले, डीएचओ डॉ.अरविंद भट्ट, सहायक प्रबंधक डॉ.सिवेन्द्र अम्बूलकर, डॉ.रोहित पराते, डॉ.जीडी पंवार होशंगाबाद, डॉ.रूपेश पद्माकर, सहायक अस्पताल प्रबंधक दशन पंद्राम, भगत सिंह उईके, मूरत उईके, मुकेश कुमरे, पदमा पंवार, धर्मेन्द्र सिंह, गुंजन कसेरा, नमिता मिश्रा, अखिलेश सैय्याम, देवेन्द्र माकोड़े, अमित राक्से, नर्सिंग ऑफिसर पुनम बैरागी एवं जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों सहित शुभचिंतकों ने बधाई दी है।

# नवीन विधि संहिता एवं प्रावधानों की जानकारी हेतु पुलिस थाना नौगांव ,धार में कार्यक्रम आयोजित

**आईजी इंदौर ज़ोन (ग्रामीण) अनुराग ने नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी**

**धार।** देश भर में एक जुलाई से लागू हुई नवीन विधि संहिता के संदर्भ में आज धार जिला मुख्यालय पर पुलिस थाना नौगांव परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता धार विधायक नीना विक्रम वर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, आईजी इंदौर ज़ोन (ग्रामीण) अनुराग, जिला विधिक सेवा सचिव उमेश सोनी, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एडीएम अश्विनी कुमार रावत सहित अन्य अधिकारीगण, एनसीसी के कैडेट एवं आम नागरिक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईजी इंदौर ज़ोन (ग्रामीण) अनुराग ने जन सामान्य को नए कानून एवं उसके प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानून का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय देना है। किसी भी थाने पर जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। पीड़ित ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कानून अंतर्गत नवीन प्रावधानों में अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में

डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है, जैसे जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो - वीडियोग्राफी कराना। पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाएगा। बदलते आपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग होगा। उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आईजी श्री अनुराग द्वारा भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य नवीन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। तीनों नवीन कानून की प्रमुख बातों को उल्लेखित करते हुए कार्यक्रम स्थल पर प्रावधानों संबंधी जानकारी की प्रदर्शनी लगाई गई थी।

## धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने फ्रेंड्स क्लब इंदौर को दी फायनल में करारी शिकस्त

**धार।** इंदौर में आयोजित क्रिकेट टुर्नामेंट में धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने फ्रेंड्स क्लब इंदौर को फायनल में करारी शिकस्त दी । धार जिला क्रिकेटएसोसिएशन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इमरान हुसेन 25 और स्वराज तड़वाल के 23 रन की बदौलत 118 रन का स्कोर खड़ा किया जवाब मैं फ्रेंड्स क्लब 19 ओवर मैं मात्र 94 रन पर सिमट गई । धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन टीम की और से सौरभ सिंह ने 2 विकेट लिये खिलाड़ीयो के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर एसोसिएशन के चेयरमैन करन सिंह पवार, अध्यक्ष प्रदीप जोशी ,उपाध्यक्ष धीरेंद्र दीघे , विनोद मित्तल, डॉ अजेश माइकल ,निखिल ग्वाल ,अमित जैन,सचिव राजेन्द्र सिंह चौहान , कोच प्रमोद पाठक, प्रमोद शर्मा , आलोक दुबे मेनेजर ,स्वराज तढवाल , आदि ने बधाई प्रेषित की! जानकारी एसोसिएशन के प्रवक्ता कुशल शर्मा ने दी।

# रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा रक्तदान शिविर एवं पौधारोपण का आयोजन

**धार।** अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी इंटरनेशनल का वार्षिक नया कार्यकाल 1 जुलाई से प्रारंभ होता है... इस अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा संपूर्ण प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है... इसी तारतम्य में रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा भोज हॉस्पिटल धार पर अपने कार्यकाल के प्रथम दिवस 1 जुलाई को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया । रक्तदाताओं में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओ सहित नगर की महिलाओ, एडवोकेट, डॉक्टर, व्यापारी सहित कई अन्य वर्ग के युवाओ ने गर्मजोशी से हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष रोटेरियन डा. मनीष सिंह, सचिव रोटेरियन विमल कुमार सिंह, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर रोटेरियन डा. अजेश मायकल , संस्थापक अध्यक्ष रोटेरियन अरुण वर्मा ने समस्त नगरवासियों के इस शिविर मे आकर मानवता की सेवा के जज्बे की प्रशंसा की एवं सभी रक्त दाता,भोज हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डा.जोसफ,रक्त विभाग के डा. अनिल वर्मा एवं उनके समस्त स्टाफ का आभार माना। रक्तदान शिविर पश्चात रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा पी जी कॉलेज धार पर पौधारोपण भी किया गया।

अमलतास, शीशम, सागवान, गुलमोहर, आम, बांस इत्यादि प्रजाति के लगभग 250 पौधों का रोपण कॉलेज के प्रिंसिपल डा. एस एस बघेल, प्रोफेसर गजेंद्र उज्जेनकर, प्रोफेसर कविता पाल, प्रोफेसर रीना चौहान एवं अन्य प्रोफेसर्स सहित कॉलेज के कई छात्रों के सहयोग द्वारा किया गया। दोनों कार्यक्रम में रोटेरियन डा. प्रदीप पाल, अलका वर्मा,डा.शशांक तिलवनकर ,ममता जोशी, सचिन बाफना, दिलीप मेघानी,डा. ऋषि तिवारी, प्रफुल्ल जैन,डा. सिल्वी सिंह, संजय लूहाड़िया, रमेश जोशी, दर्पण मंगल इत्यादि सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ। जानकारी रोटेरियन प्रफुल्ल जैन ने दी।

# नवीन आपराधिक कानून 2023 आज से लागू

## जागरूकता कार्यक्रम नवीन पुलिस थाने में संपन्न

**हीरालाल गोलानी सोहागपुर**

नवीन आपराधिक कानून 2023 आज लागू किया गया है। इस नवीन कानून के लिए नवीन पुलिस थाना परिसर में जागरूकता अभियान कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत, एसडीएम पुलिस संजू चौहान, तहसीलदार अलका एक्का, नगर निरीक्षक कंचनसिंह,नायब तहसीलदार अंजू आदि के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर निरीक्षक कंचनसिंह ने नवीन भारतीय नागरिक संहिता बीएन एस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस 2023 में किए गए परिर्वतन में बताया कि आज से भारत वर्ष में अंग्रेजी के 1861 साल पुराने कानून को देश में 163साल बाद बदल करके परिर्वतन किए गए हैं।अब तारीख पर तारीख वाले महिला कौसो दूर चल गया है। आपने नागरिकों को नवीन कानून की विस्तृत जानकारी दी। अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत ने भी नवीन कानून की बारीकियां समझाई। आपने आगे कहा कि इस कानून में वीडियो आदि सोशल नेटवर्किंग को भी साक्ष्य में शामिल किया गया है। किन्तु उससे कोई छेड़छाड़ न की गई हो।एसडीओ पुलिस संजू चौहान ने कहा कि अब देश में कहीं भी किसी भी नगर ग्राम के नागरिक की रिर्पोट दर्ज की जा सकती है। आपने कहा कि माबलाचिग, सामूहिक, अपराध आदि को नवीन कानून में स्थान दिया गया है।

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मेहरबान सिंह पटैल, जनपद पंचायत अध्यक्ष जालम सिंह , जनपद उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पटैल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटैल,नगर पंचायत उपाध्यक्ष आकाश पटैल , अनिल गहरैया, पार्षद जमील खान वकील देवान्शु शर्मा , चौबे जी नगरपालिका भारी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थीं। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गीत का आयोजन किया गया। तहसीलदार अलका एक्का ने भारत माता की जय के नारे भी लगवाए।

# एकल आरोग्य प्रकल्प का संच सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न

**नरसिंहपुर।** आरोग्य फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया संभाग महाकौशल भाग सतपुड़ा अंचल नरसिंहपुर संच करेली मिढली का संच सम्मेलन कार्यक्रम रविवार को रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समितियो द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान अमितेंद्र नारोलिया एकल अभियान अंचल संरक्षक श्रीमान प्रशांत तिवारी एकल अभियान कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सोनी एकल आरोग्य प्रकल्प के अंचल अध्यक्ष श्रीमति मिथिलेश पटेल आरोग्य प्रकल्प संच समिति अध्यक्ष श्रीमति मधुबाला जाट आरोग्य प्रकल्प करेली संच समिति अध्यक्ष श्रीमान प्रतीश भार्गव आरोग्य प्रकल्प संच समिति कोषाध्यक्ष उपस्थित हुए इसके बाद स्वास्थ्य जागरण रैली निकाली एवं सेविकाओं के द्वारा अनुभव कथन बोले फिर सेविकाओं के द्वारा जो बनो औषधि तैयार की गई थी समिति द्वारा उसका निरीक्षण किया गया इसके बाद सेविकाओं ने बीपी शुगर एचपी ऑक्सीजन तापमान वजन की जांच की जांच के पश्चात कुछ औषधि दवा दिए गए इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता श्रीमान संतोष शिववेदि संभाग आरोग्य प्रकल्प प्रमुख अरविंद लोधी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजा राम मेहरा संच कोऑर्डिनेटर मिढली अखिलेश पटेल संच कोऑर्डिनेटर करेली ऋतिक परिहार एकल ग्रामोत्थान प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर राकेश लोधी एकल अभियान संच प्रमुख बरमान एवं सभी सेविका तथा ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए।

# नव प्रवेशित छात्राओं के दीक्षारम्भ समारोह में पहुँची कलेक्टर

**नरसिंहपुर।** कलेक्टर श्रीमती शीतल पटले के मुख्य आतिथ्य में शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव/ अभिप्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। नव प्रवेशित छात्राओं का स्वागत सीनियर छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर एवं उपहार देकर किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती पटले ने महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए महाविद्यालय की छात्राओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य के निर्धारण व लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। साथ ही छात्राओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने पर बल दिया, जिससे जीवन में भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। श्री सरदार सिंह पटेल ने कहा कि महाविद्यालय में छात्राओं को जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसका अपने में उपयोगी बनाना है। श्री सुनील कोठारी ने कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश जीवन का एक नए पड़ाव होता है, जहां पर हम विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करते हैं और अपने करियर का निर्धारण करते हैं। मंच का संचालन डॉक्टर दीपिका चक्रवर्ती द्वारा किया गया।कार्यक्रम में विशिष्ट प्रभारी प्राचार्य श्री एलएन रजक, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. यतींद्र महोबे, कार्यक्रम प्रभारी डॉ. प्रज्ञा गुप्ता, महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी सोभरि, सुश्री अंशुल खरे, मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. धीरज झा, अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. नंदन शिल्पकार आदि मौजूद थे।

# ज़िला टास्क फ़ोर्स की बैठक सम्पन्न

## मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के लिए उपाय

**नरसिंहपुर।** कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ज़िला टास्क फ़ोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश बोहरे ने बताया कि वर्षा के दौरान डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर को आपके घर में या आसपास पैदा ना होने दें। डेंगू फैलाने वाली एडीज मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं और यह दिन के समय काटता है। घर की छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक बार अपने घर में रखें टीन, डब्बा व बाल्टी आदि का पानी खाली कर दें। दोबारा उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखाएं। टायरों आदि में पानी जमाव नहीं हो। पानी के बर्तन, टंकियों आदि को ढंक कर रखें। हेंडपंप के आसपास पानी एकत्र न होने दें। घर के आसपास के गड्ढों को मिट्टी से भर दें। पानी भरे रहने वाले स्थानों पर मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छर प्रतिकर्षक क्रीम, क्वाईल, शाम के समय नीम की पत्तियों का धुंआ तथा सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, जिससे मच्छर के काटने से स्वयं को बचाया जा सके। मच्छर के लार्वा को नष्टीकरण से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। बैठक में कलेक्टर ने मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के सभी उपायों का व्यापक प्रचार- प्रसार करने के निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिये। विद्यालयों में बच्चों को भी इसकी जानकारी दी जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की साफ़- सफ़ाई का विशेष ध्यान रखा जायें। जन सहभागिता के माध्यम से ही डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है।

### पांच दिन पहले हुई थी लापता

# पुलिस तलाश रही थी, तभी छात्रा वरमाला डालकर प्रेमी के साथ पहुंची थाने

**ग्वालियर (नप्र)।** ग्वालियर के मुरार से पांच दिन पहले लापता हुई 21 वर्षीय छात्रा को पुलिस तलाश पाती उससे पहले ही वह गले में वरमाला डालकर प्रेमी के साथ थाने पहुंच गई है। छात्रा ने पुलिस अफसरों को बताया है कि वह अपने दोस्त से प्यार करती है। बालिग है और दोनों ने शादी कर ली है।

छात्रा ने यह भी कहा कि वह अब अपने माता-पिता के साथ जाना नहीं चाहती है। उसने शादी की है और वह अब अपने पति के साथ रहेगी। युवती के बयान के बाद पुलिस ने उसके मायके पक्ष को भी थाना बुलवा लिया था। परिजन ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही और पुलिस ने उसे पति के साथ रवाना कर दिया। मुरार थाना प्रभारी मदनमोहन मालवीय ने बताया कि काली माता मंदिर के पास सुरैयापुरा निवासी 21 वर्षीय रजनी जाटव छात्रा है। वह बीए की पढ़ाई कर रही है। पांच दिन पहले 24 जून को वह लापता हो गई थी। रजनी के लापता होने पर परिजन ने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद मुरार थाना पहुंचकर सूचना दी थी। पुलिस ने इस मामले में तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। पुलिस छात्रा की तलाश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही रविवार को छात्रा खुद पुलिस थाना पहुंच गई। रजनी जब थाना पहुंची तो वह एक युवक का हाथ पकड़े हुए थी। दोनों के गले में वरमाला थी और रजनी मांग भी भरे हुए थी। लापता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ जो युवक है वह थाटीपुर निवासी मोहित जाटव है। वह उससे प्यार करती है और दोनों ने शादी कर ली है।

# आकांक्षी जिला एवं विकासखण्ड में सम्पूर्णता अभियान का क्रियान्वयन

**विदिशा (निप्र)।** नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलो एवं आकांक्षी विकासखण्डो के अंतर्गत संपूर्णता अभियान का क्रियान्वयन एक जुलाई से 30 सितम्बर तक संचालित करने के दिशा निर्देश प्रसारित किए है। उक्त अवधि में जिला एवं विकासखण्ड के लिए निर्धारित क्रमशः छह-छह संकेतको को संतृप्त करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही की जानी है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने शनिवार को सम्पूर्णताः अभियान के क्रियान्वयन बिन्दुओं पर आधारित समीक्षा करते हुए संबंधित विभागो के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियत अवधि 30 सितम्बर तक जिला एवं खण्ड स्तर पर जिन छह संकेतको का क्रियान्वयन किया जाना है उसमें किसी भी प्रकार की चूक ना हो। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर चार जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इसी प्रकार आकांक्षी विकासखण्ड बासौदा में पांच जुलाई को जिला स्तरीय तर्ज के अनुरूप विकासखण्ड मुख्यालय पर आयोजन किया जाएगा। कलेक्टेऊट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला स्तर पर जिन छह संकेतको की लक्षित संतृप्त तय अवधि में पूरी की जानी है उसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रथम तीन माह में प्रसव देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत कराया जाना है। टीकाकरण वाले बच्चो का शत प्रतिशत टीकाकरण किया जाना है जिसमें नौ से 11 माह के तथा बीसीजी, डीटीपी 3 . ओपीबी 3 एवं खसरा 1 इत्यादि शामिल है।

# ज़िले में लगभग 6 लाख 50 हज़ार पौधरोपण करने का लक्ष्य

### समय सीमा की बैठक संपन्न

**नरसिंहपुर।** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। मध्यप्रदेश सरकार भी पर्यावरण के प्रति गंभीर है। प्रदेश में लगभग साढ़े 5 करोड़ पौधे लगायेंगे। यह अभियान प्रदेश में एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग- अलग जिलों में चलाया जायेगा। इस कड़ी में नरसिंहपुर जिले में लगभग साढ़े छह लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व बताने के उद्देश्य से जोड़ा जायेगा। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेबसाइट पर भी फोटो अपलोड की जाएगी। इससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिजन को लेकर मां के साथ सेल्फी लें। कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए सभी विभाग की संख्या निर्धारित कर पौधरोपण करना सुनिश्चित करेंगे। पौधरोपण के पूर्व स्थल का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मात्र पौधरोपण करना ही नहीं है, बल्कि पौधों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने समय सीमा की बैठक में मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।

### सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के देयको के भुगतान में ना हो विलंब

बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटले ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की।इसमें मुख्य तौर पर राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि विभाग और अन्य विभाग शामिल थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शिकायत समय सीमा के बाहर न जाए। कलेक्टर ने खाद्य विभाग अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे हितग्राही जिन्होंने विगत छह माह से राशन नहीं लिया है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में सेवानिवृत्त होने के उपरांत शासकीय सेवक को मिलने वाले सभी देयकों का भुगतान सुनिश्चित हो, इसकी ज़िम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की होगी। आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे माह की पहली तारीख़ तक उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन प्राप्त हो। इसके लिए शत प्रतिशत सैलरी जनरेट करने का कार्य पूर्व से कर लिया जाए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना में समग्र मैपिंग एवं डीबीटी प्रतिशत कम होने पर कलेक्टर श्रीमती पटने ने अप्रसन्नता व्यक्त की।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राकेश बोहरे को निर्देशित किया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में गति लाई जाए।बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों के शासकीय कार्यालय जिन्हें डिस्मेंटल किए जाने की आवश्यकता है उसकी जानकारी प्रस्तुत करें। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम श्री मनींद्र सिंह सहित अन्य ज़िला अधिकारी मौजूद थे।

# राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ का प्राईड आफ मध्यप्रदेश - 2024 से धार की शिखा वर्मा सम्मानित

### खादी फेब्रिक पर आदिवासी महिलाओं को रोजगार देते हुए बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर के धार शहर का नाम रोशन किया शिखा ने

**धार।** ऐतिहासिक धार नगरी ने कई प्रतिभाएं दी है। इन प्रतिभाओं ने अपने कौशल और योग्यता से धार को गौरवान्वित किया है। धार शहर की ऐसी ही एक प्रतिभा शिखा वर्मा ने खादी फेब्रिक पर आदिवासी महिलाओं को रोजगार देते हुए मध्यप्रदेश में बहुत काम किया है, बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर के धार शहर का नाम रोशन किया है। फैशन डिजाइनर शिखा वर्मा की उपलब्धियों और दिये गये योगदान के फलस्वरूप राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ का प्राईड आफ मध्यप्रदेश - 2024 से सम्मानित किया गया। भोपाल में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्धयुम्न सिंह और नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने शिखा वर्मा को सम्मानित किया। धार की शिखा इन दिनों दिल्ली में आज भी अपने युनिक डिजाइन्स के साथ अपने ब्रांड नेम सत्व बाय शिखा से बिना रुके अपने परिवार एवं धार शहर का नाम रोशन कर रही है।

# जिले में अब तक 124 मिमी वर्षा दर्ज

**नरसिंहपुर।** नरसिंहपुर जिले में एक जून से एक जुलाई तक की अवधि में औसत रूप से कुल 124 मिमी अर्थात 4.88 इंच वर्षा दर्ज की गयी है। एक जुलाई की सुबह तक बीते 24 घंटे में जिले में औसतन 30.2 मिमी अर्थात 1.19 इंच वर्षा दर्ज की गई है। इस दिन तहसील नरसिंहपुर में 42 मिमी, गाडरवारा में 19 मिमी, गोटेगांव में 36 मिमी वर्षा, करेली में 33 और तेंदूखेड़ा में 21 मिमी वर्षा आंकी गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जुलाई तक तहसील नरसिंहपुर में 94 मिमी, गाडरवारा में 178 मिमी, गोटेगांव में 179 मिमी, करेली में 52 और तेन्दूखेड़ा में 117 मिमी वर्षा आंकी गई है। इसी अवधि में पिछले वर्ष जिले में औसतन 354 मिमी वर्षा हुई थी। इस अवधि में पिछले वर्ष तहसील नरसिंहपुर में 439 मिमी, गाडरवारा में 386 मिमी, गोटेगांव में 220 मिमी, करेली में 419 मिमी और तेन्दूखेड़ा में 306 मिमी वर्षा हुई थी।

नर्सिंग घोटाले पर हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही आज तक स्थगित

# नेता प्रतिपक्ष बोले- 300 करोड़ की वसूली हुई, मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करें

## कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर विधानसभा पहुंचे, नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया, मामला कोर्ट में है इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सिंघार ने एक बार फिर चर्चा की बात कही। इस पर सीएम मोहन यादव ने कहा, नियम प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य परंपरा में चर्चा के लिए तैयार हैं। उत्तेजना से हम बात सुन नहीं सकते। हम सीधी साधारण भाषा बोलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह आप दोनों ने मुझ पर छोड़ने के लिए कहा है तो कल इसका ध्यान रखेंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा होगी।कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे थे। वे हाथों में नर्सिंग घोटाला लिखे कागज पकड़े थे।

### सत्र के लिए कुल 4287 सवाल आए

बजट सत्र में विधायकों ने कुल 4287 सवाल सरकार से पूछे हैं। इनमें 2108 सवाल तारांकित और 2179 सवाल अतारांकित हैं। ऑनलाइन सवालों की संख्या 2386 है जबकि 1901 सवाल ऑफलाइन आए हैं। ध्यानाकर्षण की 163, स्थगन प्रस्ताव की 1, अशासकीय संकल्प की 27 तथा शून्यकाल की 43 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं।

### कांग्रेस विधायकों ने एंट्री ही एप्रिन पहनकर की थी

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर पहुंचे और नर्सिंग घोटाले को लेकर नारेबाजी की। कमलनाथ ने कहा, प्रश्न ये नहीं है कि प्रदेश में घोटाले हुए, प्रश्न ये है कि प्रदेश में कौन सा घोटाला नहीं हुआ। वहीं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले- विपक्ष के पास न मुद्दा बचा है न कोई बोलने वाला। विपक्ष अगर स्थगन प्रस्ताव लाता है तो हम उसका जवाब देने को भी तैयार हैं।

### नेता प्रतिपक्ष बोले- नर्सिंग घोटाले में 300 करोड़ की वसूली हुई

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के अंदर 300 करोड़ की वसूली की गई। मंत्री सारंग ने अपने हिसाब से कानून बनाए। फेरबदल किए। कानून ने फटकार लगाई, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। आगे घोटाले न हों, इसको लेकर हम विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांक कर रहे हैं।

### कांग्रेस ने नारेबाजी की, मंत्री सारंग को बर्खास्त करने की मांग

विधानसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई तो विपक्ष बाहर आ गया। यहां गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

संसद में राहुल गांधी पर भड़के शिवराज

# राहुल बोले- किसानों को एमएसपी नहीं दी; कृषि मंत्री ने कहा- ऐसा है तो साबित करें

**भोपाल (नप्र)।** लोकसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने-सामने आ गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। जिस पर शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी सोमवार को पहली बार संसद में बोले। उन्होंने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। आपकी सरकार ने कह दिया कि किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। राहुल की इस बात पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। उन्होंने राहुल को इस बयान को साबित करने की चुनौती दे डाली।राहुल गांधी ने कहा- 700 किसान शहीद हुए, हमने कहा संसद में मौन होना चाहिए। आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है। आपके मुताबिक यह किसान नहीं थे, आतंकवादी थे।राहुल गांधी ने आगे कहा- किसानों ने सिर्फ यह कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए का जब अरबपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो थोड़ा सा हमारा भी कर्जा माफ कर दीजिए। किसानों ने कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। आप लोगों ने कहा कि किसान का कर्ज माफ नहीं होगा। और एमएसपी नहीं मिलेगी।

### शिवराज बोले- गलत बयान दे रहे राहुल

राहुल गांधी की बात सुनकर शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये गलत बयानी कर रहे हैं। सरकार एमएसपी दे रही है। ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। यदि नहीं दी जा रही है तो यह बात सत्यापित करें। शिवराज सिंह ने कहा- ये गलत बयानी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। अभी 14 खरीफ की फसलों के एमएसपी के रेट तय किए हैं। शिवराज ने राहुल गांधी से कहा कि वे बताएं कि जब उनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी थी उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। यह गलत बयानी कर रहे हैं। यह इस बात को सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही।

# म.प्र.में 1 जुलाई से आरटीओ चेक पोस्ट बंद

## 45 चेक पाइंट बनाकर होगी जांच, करप्शन रोकने बॉडी वार्न कैमरे से लैस रहेंगे कर्मचारी

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश में एक जुलाई से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां (आरटीओचेक पोस्ट) बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक

पाइंट बनाए जाएंगे। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जांच की जाएगी। सरकार ने रविवार को इसके आदेश जारी कर दिए है। दरअसल, प्रदेश में संचालित आरटीओ चेक पोस्ट पर लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद रविवार को परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है।

**ट्रक ऑपरेटर बोले- 70 फीसदी तक समस्या खत्म:** इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा, नई व्यवस्था से ट्रक ऑपरेटरों की समस्या 70 फीसदी तक खत्म हो जाएगी। इससे न सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों को फायदा होगा बल्कि हाईवे पर भी इकोनॉमी बेहतर होगी। बाहर की गाड़ियां आएंगी तो ढाबे, पेट्रोल पम्प पर भी कारोबार बढ़ेगा।हालांकि, उन्होंने कहा कि एमपी में जल्द से जल्द मानव रहित व्यवस्था बनाकर टेक्नोलॉजी के ?जरिये गुजरात से भी अच्छा मॉडल बनाया जाना चाहिए।

**211 होमगार्ड्स के जवानों की जिले वार प्रतिनियुक्ति की गई:** मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में संचालित परिवहन चेक पोस्ट की जगह 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट और 94 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट के लिए 211 होमगार्ड्स के जवानों की जिले वार प्रतिनियुक्ति की गई है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी ड्यूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा।

**गुजरात पैटर्न पर होगी जांच, बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगा अमला:** परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों को छोड़कर बाकी अमले की भर्ती जल्दी होगी। तब तक प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ की व्यवस्था होगी। परिवहन चौकी बंद होने के बाद गुजरात के पैटर्न पर हाईटेक तरीके से वाहनों की नियमानुसार जांच की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों की ओवर लोडिंग की जांच करने के लिए मोबाइल वेइंग मशीन यानी चलित धर्म कांटे भी मंगाए जाएंगे। परिवहन चेक पॉइंट पर वाहन चालकों को परेशानी ना हो और सिस्टम में पारदर्शिता रहे। इसके लिए स्टाफ को बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस किया जाएगा।

# नया कानून लागू, ग्वालियर में रात 12.24 बजे हुई एफआईआर

## आईजी-डीआईजी बोले-अपराध से निपटने के लिए आया अब नया कानून

**ग्वालियर (नप्र)।** ग्वालियर सहित देशभर में (एक जुलाई) से नया कानून लागू हो गया है। नए कानून में धाराएं बदल गई हैं। नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर ग्वालियर के हजीरा थाना में रात 12.24 बजे दर्ज हुई है, जबकि यह घटना एक जुलाई की रात 12.05 बजे हजीरा यादव धर्मकांटा की है।

जिस पर पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 303 (2) एस 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। पहला मामला सौरभ नरवरिया निवासी हजीरा यादव धर्मकांटा की ओर से बाइक चोरी का केस दर्ज कराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर एक्स पर अपडेट किया है। सोमवार को ग्वालियर के थानों में नए कानून के लागू होने पर थानों में कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। हजीरा थाना में आईजी अरविंद सक्सेना, एसपी धर्मवीर सिंह मुख्य समारोह में शामिल हुए हैं। साथ ही पड़ाव थाना में पूर्व मंत्री माया सिंह, डीआईजी कृष्णावेणी देशाबंधु शामिल हुई हैं। इस दौरान आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा कि बदले समय में अपराध के तरीके बदल गए हैं। इसलिए नया कानून आया है। इससे जनता को जल्द लाभ मिलेगा और अपराधी बच नहीं सकेंगे।

**नए कानून में आमजन को राहत:** आईजी ग्वालियर सक्सेना ने कहा कि समय बदल रहा है। अपराध का तरीका भी बदला है। अपराधी कानून से बचने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनसे निपटने में पुराने कानून में कुछ अड़चनें थीं। अब नया कानून आया है, जिससे आमजन को राहत रहे और अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आया जा सके। नए कानून में आमजन को राहत है तो पुलिसकर्मियों को अपराधियों से निपटने के लिए कुछ पॉवर मिले हैं, जो जनता के काम आएंगे।

### एसपी बोले- अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नया कानून

इस मौके पर पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह ने कहा कि नया कानून अपराधियों पर नकेल कसने के लिए है। नए कानून से अब जनता को लाभ मिलेगा और इनका क्रियान्वन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिससे जनता को सुलभ और शीघ्र लाभ मिल सके। फरियादी पुलिस के पास उसी समय आता है, जब वह परेशानी का शिकार होता है। अब नया कानून आने से उन्हें वर्षों न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समय सीमा में उनकी समस्या का निराकरण हो सकेगा। कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया है, जैसा कानून लाने का उद्देश्य है।

**डीआईजी बोलीं- शिकायत पर तीन दिन में एफआईआर करनी ही होगी:** पड़ाव थाना में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी कृष्णा वेणी देशावतु ने कहा कि तीनों नए कानून जनता के हित में हैं और इनके आने से जनता को राहत और अपराधियों में खौफ रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के आने से अब पुलिस जनता के हित में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है, साथ ही अब फरियादी को गवाही देने के लिए थाने आने की जरूरत नहीं है, वह अपने बयान ऑनलाइन भी दे सकता है। जिससे मामलों को निपटाने में रफ्तार आएगी। अब शिकायत मिलने पर तीन दिन में एफआईआर करनी होगी, जिससे फरियादी को मामला दर्ज कराने के लिए अब थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

### थाना में आम जनता का हुआ स्वागत, समझाया नया कानून

सोमवार को नया कानून लागू होने पर हर थाना में आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय जनता को बुलाया गया था। सोमवार को जब स्थानीय लोग अपने-अपने निकटतम थाना में पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उनका दिल से स्वागत किया। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को नए कानून के संबंध में समझाया।

### पड़ाव थाने में डीआईजी ने कराई पहली एफआईआर

सोमवार को पड़ाव थाना की पहली एफआईआर डीआईजी कृष्णा वेणी देशावतु ने नए कानून के तहत कराई है। जिसमें फरियादी अंशु शर्मा की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया। यह पड़ाव थाना की पहली एफआईआर मानी गई है।

# उपचुनाव के प्रचार के दौरान सांसद ने चलाया हल

## छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने बटका खापा में किसान के साथ की खेत की जुताई

**छिंदवाडा (नप्र)।** छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं इसी बीच आज उन्होंने आदिवासी अंचल बटका खापा के टाटी घाट ग्राम में किसान महेश उइके के खेत में हल चलाया। दरअसल वह इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं तभी टाटी घाट के पास जब वह अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। तभी एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था जिसे देखकर विवेक बंटी साहू ने अपना काफिला रुकवाया और अभी सीधे खेत में पहुंच गए जहां उन्होंने खेत में किसान के साथ हल चलाया।

# बारिश ने सुधारी शहर की आबोहवा,एक्यूआई 20 पर पहुंचा

- सबसे कम प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भोपाल म.प्र. का पहला और देश में छटवां शहर

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में हो रही बारिश के चलते शहर की हवा साफ हुई है। रविवार को इस साल का सबसे कम 20 एक्यूआई दर्ज किया है। इसके अनुसार भोपाल देश के सबसे कम प्रदूषित शहरों की लिस्ट में छठवें नंबर पर है, वहीं प्रदेश में यह सबसे अव्वल है। इससे पहले देश में मिजोरम के अइजोल में 11, सिक्किम गंगटोक 13, असम के गुवाहाटी में 17, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 16, , उत्तर प्रदेश के बरेली में 19 में एक्यूआई दर्ज किया गया है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में 542 अलग अलग लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम हैं, जिस पर यह 30 जून को दर्ज किया गया है।

### यह है कारण

पर्यावरण के जानकार और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर ब्रजेश शर्मा की माने तो आमतौर पर एक दो दिन की बारिश इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते एक्यूआई इतना अधिक गिरा है। बारिश से डस्ट पार्टिकल जमीन में नीचे बैठ गए हैं। इस वजह से पर्यावरण परिसर यानी शाहपुरा इलाके में एक्यूआई तेजी से गिरा है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बनती है। इससे जहां एक तरफ डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नहीं उठ पाते तो दूसरी तरफ हानिकारक गैसे भी आसानी से वायुमंडल में डिजॉल्व हो जाती हैं।

# पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, वाटर कैनन से खदेड़ा

## नीट-नर्सिंग घोटाले पर प्रदेशभर में प्रदर्शन, मंदसौर में पुतला फूंकते समय नेता आग में झुलसे

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला और नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। इस दौरान जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन्हें खदेड़ा। इधर, मंदसौर में पुतला दहन करते समय कांग्रेस नेता के कुर्ते में आग लग गई। इससे वे झुलस गए। जबलपुर के गांधी टाउन हॉल से कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही कलेक्ट्रेट परिसर के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें घंटाघर चौक पर रोक लिया। कांग्रेस का उग्र आंदोलन देख पुलिस ने वाटर कैनन से उन पर पानी की बौछार की। कांग्रेस कार्यकर्ता भी बेरिकेड्स पर चढ़ गए और आगे बढ़ने की कोशिश की। करीब एक घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घंटाघर चौक पर रोक दिया। यहां उनकी पुलिस से झड़प हो गई। जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ा। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि जब-जब छात्रों पर अन्याय हुआ है, तब-तब भाजपा सरकार ने पुलिस का सहारा लिया और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। लेकिन सरकार ये समझ ले कि कांग्रेस पार्टी की आवाज किसी भी कीमत पर दबेगी नहीं और हमेशा छात्रों के हित में सड़क पर रहेगी। कांग्रेस का आरोप है कि नीट घोटाले को लेकर भाजपा सरकार दोषी है। भर्ती परीक्षाओं में लगातार घोटाले किए जा रहे हैं। रसूखदार लोगों से लाखों-करोड़ों रुपए बटोर कर पेपर लीक कर देते हैं। सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है।

### मंदसौर-पुतला फूंक रहे थे, कांग्रेस नेता के कुर्ते में लगी आग

मंदसौर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर के कुर्ते में आग लग गई। हालांकि कार्यकर्ताओं ने तत्काल आग बुझा ली। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रदर्शन के दौरान मंत्री का पुतला जला रहे थे। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओ के बीच कुछ देर पुतले की छीना झपटी चलती रही। मौके पर फायर फाइटर ने पानी की बौछार डालकर पुतले की आग बुझाई। इसी दौरान कार्यकर्ता एक और पुतला ले आए और उसे दहन किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष के कुर्ते में आग लग गई जिसे तुरंत बुझाया गया। हालांकि इस दौरान उनकी गर्दन मामूली रूप से झुलस गई।

### इंदौर- कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन

इंदौर में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।